



04 - जिनेवा देगा प्लास्टिक प्रदूषण से मुक्ति की राह?



05 - प्राकृतिक संपदा के देहन से खोखला विकास

A Daily News Magazine

मोपाल

गुरुवार, 7 अगस्त, 2025



मोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 22, अंक 329, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रु. 2



06 - आगनी 4 दिन बारिश के आसार नहीं, लोग गर्मी-उमस से परेशान...



07 - आपदा प्रबंधन को छोड़ बाकी कार्यों से अफसरों की दूरी



subahsaverenews@gmail.com



facebook.com/subahsaverenews



www.subahsavere.news



twitter.com/subahsaverenews

सुप्रभात

मैं अपने दोस्त के हाथों मारा गया। मरने से पहले लोग क्या सोचते हैं? बचपन की बातें, जवानी के सुनहरे दिन या कुछ और- मुझे नहीं पता।

मरने से पहले, जब मैंने अपने दोस्त के हाथ में तेज चाकू देखा, तो मैंने एक शानदार मौत के बारे में सोचा था। इसलिए मैंने चुपचाप अपना जीवन अपने दोस्त को सौंप दिया; जैसे मैंने धीरे से अपने प्रिय के खोपे पर गुलाब पहनाया हो।

मैं मारा गया। खत्म हो गए मेरे दोस्त के साथ कई गुलाबी संवाद।

- **हीरेन भट्टाचार्य**

कुबेरेश्वर धाम आए दो और श्रद्धालुओं की मौत, 3 घायल

पंडित प्रदीप मिश्रा ने निकाली कांवड़ यात्रा, 2 दिन में 4 लोगों की गई जान



सीहोर (नप्र)। सीहोर में बुधवार को पंडित प्रदीप मिश्रा के कुबेरेश्वर धाम में कांवड़ यात्रा में शामिल होने

आए दो लोगों की मौत हो गई। मृतकों के नाम चतुर सिंह (उम्र 50 वर्ष) पिता भूरा पांचवल गुजरात और ईश्वर

सिंह (उम्र 65 वर्ष) रोहतक हरियाणा के निवासी हैं।

बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति की मौत कुबेरेश्वर धाम में अचानक चक्कर आकर गिरने से हुई है, जबकि दूसरे व्यक्ति की मौत एक होटल के सामने खड़े-खड़े गिर जाने से हुई है।

वहीं हरियाणा की सुनीता नाम की एक महिला कावड़ ले जाते समय भोपाल-इंदौर हाईवे पर गिरने से घायल हो गई। कुबेरेश्वर धाम में मथुरा से आई पूजा सैनी नाम की महिला भी गिरने से जख्मी हो गई। नागपुर की मनीषा भी अचानक धाम में पास बेहोश हो गई। इन्हें अस्पताल लाया गया है।

मंगलवार को कुबेरेश्वर में रुद्राक्ष बंटते ही मची थी भगदड़

हम परिवार के साथ पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा सुनने यहां आए थे। यहां कोई सुविधा नहीं है। कोई सिक्योरिटी नहीं है। रुद्राक्ष बंटना शुरू हुआ तभी भगदड़ मच गई। चारों तरफ जो ये बिल्डिंग बनी है, ये बिजनेस के लिए है या जनता के लिए? यहां तो रोड पर नहाने तक के 50 रुपए लेते हैं। सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में यूपी के मेरठ से आई सूरज बाई गुरसे में आकर ये बात कहती हैं। यहां मंगलवार को जब भगदड़ में दो महिलाओं की मौत हुई तब वे वहीं थीं। बदइतजामी की लेकर ऐसा ही गुरसा दूसरे लोगों में भी है। भारी भीड़ जुटने की जानकारी के बावजूद न प्रशासन ने पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की न कुबेरेश्वर धाम से जुड़े लोगों ने। नतीजा- दो मौतें। बुधवार को प्रदीप मिश्रा की कांवड़ यात्रा में शामिल होने के लिए देशभर से श्रद्धालु इकट्ठा हुए हैं। मंगलवार को धाम में बने रुद्राक्ष वितरण केंद्र के सामने सुबह 5 बजे से ही लोगों की भीड़ जमा होनी शुरू हो गई। रुद्राक्ष वितरण का समय सुबह 10 से शाम 5 बजे तक रहता है। जैसे ही 10 बजे हादसा हुआ।

स्वाधीनता दिवस हमारी राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

जन-जन को जोड़ें आजादी पर्व से

● आयोजन और प्रबंधन में कोई कमी नहीं रहे ● मुख्यमंत्री का जनता के नाम संदेश का सभी जिलों में होगा लाइव प्रसारण, स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों की समीक्षा

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि स्वतंत्रता दिवस केवल एक पर्व नहीं, बल्कि यह हमारी राष्ट्रीय अस्मिता, स्वाभिमान और गौरव का प्रतीक है। यह अवसर हमें हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, बलिदान और योगदान को स्मरण करने तथा उनके दिखाए मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव बुधवार को स्वतंत्रता दिवस समारोह-2025 के आयोजन से जुड़ी तैयारियों की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में तय किया गया कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रदेश की जनता के नाम संदेश का सभी जिलों में होने वाले जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में लाइव प्रसारण किया जाएगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश की जनता के नाम संदेश का लाइव प्रसारण पूरा होने के बाद जिलास्तरीय कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अपने संबोधन में जिले में संचालित पल्लेगशिप योजनाओं, विकास कार्यक्रमों, जिले में आए निवेश, कृषि एवं सिंचाई के क्षेत्र में हुए विकास और अन्य उल्लेखनीय



गतिविधियों के बारे में भी नागरिकों को जानकारी देंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य एवं जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन पूरे हर्ष उल्लास, गरिमा और जन सहभागिता के साथ हो। विशेष रूप से युवा वर्ग में देशभक्ति की भावना जागृत करने के उद्देश्य से सांस्कृतिक

कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाये।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने राज्यस्तरीय समारोह स्थल पर बैठक व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था एवं यातायात प्रबंधन से जुड़ी तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने कहा कि समारोह में लोकतंत्र सेनानियों, दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

है। लेकिन आज भाषा की विकृति मानव जीवन के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। संवादों में गालियां, हिंसा प्रेरक शब्द, अश्लीलता परोसने वाले शब्द, हमेशा से समाज के लिए अनैतिक और अप्राज्ञ समझे जाते थे। लेकिन आज फिल्मों से लेकर सोशल मीडिया पर बढ़ते हिंसक दृश्य; अश्लील और अनैतिक संबंध, मनोरंजन के नाम पर परोसे जा रहे हैं। इन शब्दों और बिंबों का मानव जीवन और मनोमस्तिष्क पर गहरा असर हो रहा है। खासकर, नई पीढ़ी के किशोरवय बच्चों में बढ़ते हिंसा और सेक्स के प्रति रुझान ने समाज को बड़े पैमाने पर दूषित किया है।

भाषा सिर्फ शब्दों और संवादों में नहीं होती, दृश्यों की भी एक भाषा होती है। पोनोग्राफी से लेकर वेब सीरीज जैसे फिल्मी दृश्यों ने समाज और नई पीढ़ी पर गहरा असर डाला है। इससे रिशतों की मर्यादा बिखरी है। सामाजिक संबंध टूटे हैं। आधुनिक मूल्यों और तर्कों के आधार पर विकसित होने वाले संबंध आज स्वार्थ और अहंकार में डूब रहे हैं। इसलिए भाषा के इस बढ़ते असर को प्रदूषण की तरह देखा जा रहा है, जो पर्यावरण प्रदूषण की तरह ही मानव जीवन पर प्रतिकूल असर डाल रहा है।

विश्व प्रसिद्ध भाषाविद जॉर्ज स्टेनर कहते हैं कि 'दुनिया जैसी है, वैसी उसे स्वीकार करने का मनुष्य का मुख्य उपकरण भाषा है।' दुनिया को अभिव्यक्त करने का माध्यम भाषा है। प्रत्येक भाषा की अपनी एक विश्वदृष्टि है। हिन्दी की विश्वदृष्टि बेहद उदार और समावेशी रही है। लंबे समय से हिन्दी इस देश की संपर्क भाषा है। लेकिन साहित्यिक भाषा बनने का इसका इतिहास डेढ़ शताब्दी से अधिक पुराना नहीं है। हिन्दी सिर्फ एक भाषा नहीं है बल्कि 46 बोलियों का परिवार है। हिन्दी स्थानीय बोलियों और देशी-विदेशी भाषाओं के शब्दों से समृद्ध

होती रही है। पिछली एक सदी में हिन्दी की जितनी भाषिक समृद्धि हुई है, उसके मुकाबले 21वीं शताब्दी में हिन्दी की समृद्धि अधिक गत्यात्मक है। लेकिन भूमंडलीकरण की सांस्कृतिक प्रक्रिया और सूचनाओं के बेतरतीब बढ़ते प्रभाव के कारण हिन्दी का स्वभाव दूषित हुआ है। अपसंस्कृति को बढ़ावा मिला है।

भूमंडलीकरण के चलते भौतिकवाद और उपभोक्तावाद बढ़ा है। पश्चिमीकरण के बढ़ते प्रभाव के कारण भारतीय संस्कृति दूषित हुई है। लेखक हो या सामाजिक कार्यकर्ता इस फेसबुकिया दौर में सबकी प्रदर्शनप्रियता बढ़ी है। काम को प्राथमिकता देने के बजाय आत्म प्रदर्शन और महत्वाकांक्षाओं का असर सीधे तौर पर दिखाई पड़ रहा है। हिन्दी की भाषिक संस्कृति पर भी इसका प्रभाव हुआ है। अंग्रेजी शब्दों का बोलबाला बढ़ रहा है। सामाजिक प्रतिबद्धता के बजाय लेखक पुरस्कार पाने और फैन बनाने के लिए बेताब नजर आते हैं। रील्स की दौड़ में नेता, अभिनेता ही नहीं लेखक भी शरीक हो गए हैं। इसलिए उनकी रचनाशीलता प्रभावित हुई है। संवेदना, शिल्प और भाषा पर भी गहरा असर देखा गया है। लोकप्रिय साहित्य के नाम पर चलताऊ कथाएं लिखी जा रही हैं। हास्य के नाम पर फूहड़ता, प्रेम के नाम पर यौनिकता और संघर्ष के नाम पर गैंगवार दिखाया जा रहा है। इससे अपभाषा की संस्कृति बेलागाम हुई है। रही सही कसर बॉलीवुड की फिल्मों, विज्ञापनों और रील्स के जरिए परोसी जा रही अश्लीलता ने पूरी कर दी है।

पिछले एक- डेढ़ दशक में सोशल मीडिया ने पूरे समाज को अपनी चपेट में ले लिया है। कुछ आंदोलन, कुछ शायदियां और कुछ बहसों को छोड़ दें तो सोशल मीडिया ने लोगों के मस्तिष्क पर तीव्र हमला किया है। मोबाइल के जरिए सोशल मीडिया, हमारे बेडरूम से

लेकर किचन और बाथरूम तक घुस गया है। सोशल मीडिया फेक न्यूज से लेकर मनोरंजक और उत्तेजक रील्स से भरा हुआ है। इसने समाज की हर पीढ़ी को प्रभावित किया है। लेकिन बच्चों और नौजवानों को इसका एडिक्ट बना दिया है। सोशल मीडिया के एडिक्शन ने लोगों के मस्तिष्क पर जो हमला किया है, उससे पढ़ाई-लिखाई ही नहीं प्रभावित हुई है बल्कि उनकी भाषा और संस्कार भी विकृत और दूषित हुए हैं। सोशल मीडिया पर भौंडे गाने, अश्लील नृत्य और सेक्स वीडियो की भरमार है। इससे किशोरों और नौजवानों में यौन कुंठा पैदा हुई है। महिलाओं के प्रति उनकी भाषा अश्लील और हिंसक हुई है। दरअसल, हमारी पीढ़ी सोशल मीडिया से बेहद आक्रांत है। इसलिए उसके लिखने और बोलने में अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग तेजी से बढ़ा है। हिन्दी और स्थानीय भाषाओं के शब्दों की उपलब्धता के बावजूद अंग्रेजी भाषा के प्रयुक्त शब्दों पर सोशल मीडिया का सीधा असर दिखाई देता है। इससे हिन्दी भाषा दूषित ही नहीं संकीर्ण भी हुई है।

अमेरिका और यूरोप जैसे पूंजीवादी साम्राज्य, एशिया और अफ्रीका के विकासशील और गरीब देशों पर सांस्कृतिक वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं। दुनिया की सैकड़ों भाषाएं मरने की कगार पर हैं। अपभाषा के चलते भाषा में आ रही संकीर्णता और संवेदना के ह्रास से मुक्ति के लिए प्राथमिक स्तर पर मूलगामी वैचारिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। साहित्य और कलाओं के प्रचार-प्रसार के जरिए सोशल मीडिया के हमले का मुकाबला किया जा सकता है। देशी भाषाओं की उर्जा और विकास के लिए सरकारी स्तर पर ठोस प्रयास किए जाने चाहिए।

(सत्य हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

ट्रम्प ने भारत पर 25 फीसदी एक्सट्रा टैरिफ लगाया

अब कुल 50 फीसदी टैरिफ, आदेश पर किए दस्तखत

वॉशिंगटन (एजेंसी)। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने भारत पर 25 फीसदी एक्सट्रा टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने गुरुवार को इससे जुड़े एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किए। यह आदेश 27 अगस्त से लागू होगा। इससे पहले उन्होंने 30 जुलाई को 25 फीसदी टैरिफ का ऐलान किया था। अब तक अमेरिका की तरफ से भारत पर कुल 50 फीसदी टैरिफ लगेगा। ट्रम्प ने रूसी तेल खरीद की वजह से भारत पर यह ऐक्शन लिया है। उन्होंने एक दिन पहले कहा था भारत रूसी तेल खरीद कर यूक्रेन युद्ध जारी रखने में रूस की मदद कर रहा है। इस वजह से अमेरिका भारत पर ऐक्शन लेगा। ट्रम्प ने आज के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में लिखा है- भारत सरकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से रूस से तेल आयात कर रही है। ऐसे में अमेरिका में दाखिल होने वाले भारत के सामानों पर 25 फीसदी का एक्सट्रा टैरिफ लागू होगा। यह शुल्क 21 दिन बाद से लागू होगा।



‘आफत’ बनी बारिश, दरक रहे हैं पहाड़

● हिमाचल के किन्नौर में 2 श्रद्धालुओं की मौत ● किन्नर कैलाश यात्रा रुकी, 413 तीर्थयात्री बचे



नई दिल्ली (एजेंसी)। पहाड़ों पर मानसून की बारिश आफत लेकर आई है। हिमाचल प्रदेश में मंगलवार रात से जारी भारी बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। किन्नौर जिले में सालाना होने वाली किन्नर कैलाश यात्रा पर गए दो श्रद्धालुओं की बाढ़ में बहने से मौत हो गई। अचानक आई बाढ़ से यात्रा रूट पर दो पुत्र भी बह गए। बाकी का रास्ता

उत्तराखंड के पौड़ी में बाढ़ फटा, संकट बढ़ा

भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके कारण यात्रा रोक दी गई है। कई श्रद्धालु फंसे हुए हैं। भारत-तिब्बत सीमा पुलिस की टीम ने जिपलाइन की मदद

500 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। शिमला, मंडी, सोलन और कुल्लू जिले में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। उत्तराखंड में बुधवार को भी भारी बारिश जारी है।

11 जवानों समेत 100 से ज्यादा लापता, एक शव बरामद

देहरादून (एजेंसी)। उत्तराखंड में उत्तरकाशी के धराली गांव में मंगलवार दोपहर करीब 1.45 बजे बाढ़ लफटने से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। बुधवार सुबह रेस्क्यू-सर्व ऑपरेशन के दौरान एक डेडबॉडी बरामद की गई। उसकी पहचान की जा रही है। 100 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। कल से लेकर अभी तक 150 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आर्मी की टीमें बचाव कार्य में जुटी हैं। बुधवार सुबह पीएम मोदी ने उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात की। इसके बाद धामी ने धराली और दूसरी जगहों का एरियल सर्वे किया। उन्होंने अधिकारियों के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर मीटिंग भी की। गंगोत्री तीर्थयात्रियों के प्रमुख पड़ाव धराली गांव के बाजार-मकान, होटल बह गए खीर गंगा नदी में पहाड़ों से बहकर आए मलबे से बड़े, सिर्फ 34 सेकेंड में ये बर्बादी हुई।

से 413 तीर्थयात्रियों को बचाया है। मंगलवार रात में चंडीगढ़-मनाली नेशनल हाईवे पर भी लैंडस्लाइड में मलबा गिरने से दो महिलाएं सब गइं। इनमें से एक महिला का शव बरामद हो चुका है। जबकि दूसरी

मुख्यमंत्री प्रदेश की सभी लाइली बहनों को देंगे रक्षाबंधन का शगुन 07 अगस्त को प्रत्येक लाइली बहना के खाते में आएंगे 1500 रुपये

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मुख्यमंत्री लाइली बहना योजना के तहत गुरुवार 07 अगस्त को जगदह जिले के नरसिंहगढ़ से प्रदेश की 1 करोड़ 26 लाख 89 हजार 823 लाइली बहनों के खातों में 1 हजार 859 करोड़ 1 लाख 32 हजार 350 रुपये की राशि का अंतरण करेंगे। इस बार लाइली बहनों को नियमित किश्त 1250 रुपये के अतिरिक्त रक्षाबंधन के शगुन के रूप में 250 रुपये भी दिये जाएंगे। इस प्रकार प्रत्येक लाइली बहना को रक्षाबंधन के पूर्व 1500 रुपये मिलेंगे।

क्रिकेटर यश दयाल की गिरफ्तारी रोकने से हाईकोर्ट का इनकार

कोर्ट ने कहा-रेप पीड़ित नाबालिग है

जयपुर (एजेंसी)।आईपीएल चैंपियन आरसीबी के तेज गेंदबाज यश दयाल को नाबालिग से रेप के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। जयपुर में जस्टिस सुदेश बंसल की अदालत ने कहा-पीड़ित नाबालिग है, इसलिए गिरफ्तारी और



पुलिस कार्रवाई पर रोक नहीं लगा सकते। अदालत ने केस डायरी तलब की है। अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी। बहस के दौरान क्रिकेटर के वकील कुणाल जैमन ने कहा-हमारे खिलाफ गाजियाबाद में भी एक लड़की ने रेप केस किया था। जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। उसके 7 दिन बाद ही जयपुर में दूसरी लड़की ने केस दर्ज करवा दिया। इस मामले में पूरा गिरोह सक्रिय है। जो इस तरह के मुकदमे दर्ज करवाकर ब्लैकमेल करना चाहता है। जयपुर की लड़की ने मामला दर्ज कराया है।

महंगे नहीं होंगे लोन, ईएमआई भी नहीं बदलेगी

आरबीआई ने रेपो रेट में नहीं किया है बदलाव

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने इस बार रेपो रेट में बदलाव नहीं किया है। इसे 5.5 फीसदी पर जस का तस रखा है। यानी लोन महंगे नहीं होंगे और आपकी ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी।



आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज यानी 6 अगस्त को इसकी जानकारी दी। गवर्नर ने कहा कि कमेटी के सभी मेंबर्स ब्याज दरों में स्थिर रखने के पक्ष में थे। टैरिफ अनिश्चितता के कारण ये फैसला लिया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई जिस रेट पर बैंकों को लोन देता है उसे रेपो रेट कहते हैं।

जन-धन खाते की फिर करानी होगी केवायसी

योजना के 10 साल पूरे

नई दिल्ली (एजेंसी)। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आज 3 बदलावों की घोषणा की है। ये बदलाव जनधन स्कीम, इश्योरेंस वलेम रूल्स और निवेश से जुड़े हैं। जन धन योजना को 10 साल पूरे होने वाले हैं, और बहुत से अकाउंट होल्डर्स को अपना केवायसी अपडेट कराना है। इसे देखते



हुए,आरबीआई ने बैंकों को 1 जुलाई से 30 सितंबर तक ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष कैंप लगाने का निर्देश दिया है। इन कैंपों में लोग अपना खाता अपडेट करा सकेंगे, नए खाते खुलवा सकेंगे, और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जैसी सरकारी योजनाओं की जानकारी भी ले सकेंगे।आरबीआई ने डेड अकाउंट होल्डर्स के वलेम्स सेंटलमेंट के लिए यूनिफॉर्म प्रोसेस की घोषणा की है।

गलवान झड़प के बाद पहली बार चीन जाएंगे मोदी

● एससीओ समिट में होंगे शामिल,11 साल में 5 बार गए पीएम

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ समिट में शामिल होने के लिए चीन जाएंगे। यह दौरा 31 अगस्त और 1 सितंबर को होगा। यह 2020 में गलवान घाटी में भारत-चीन सैन्य झड़प के बाद मोदी की पहली चीन यात्रा होगी।

मोदी इससे पहले 2018 में वहां गए थे। प्रधानमंत्री के तौर पर पीएम मोदी का यह छठा चीन दौरा होगा, जो 70 सालों में किसी भी भारतीय पीएम की सबसे ज्यादा चीन यात्रा है।

चीन से पहले पीएम मोदी 30 अगस्त को जापान पहुंचेंगे। यहां वो भारत-जापान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पिछले महीने विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने चीन का दौरा किया था, जहां उन्होंने राष्ट्रपति शी जिनपिंग और विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। जयशंकर ने जल संसाधन डेटा शेयर करने, व्यापार प्रतिबंधों, एलएसी पर तनाव कम करने और आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ



कड़ा रख अपनाने जैसे मुद्दों पर बात की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस मुलाकात ने मोदी की चीन यात्रा का रोडमैप तैयार किया था। मोदी और जिनपिंग ने आखिरी बार अक्टूबर 2024 में रूस के कजान में ब्रिक्स समिट के दौरान मुलाकात की थी। इस दौरान दोनों के बीच द्विपक्षीय बातचीत भी हुई थी। 50 मिनट की बातचीत में पीएम मोदी ने कहा था कि सीमा पर शांति

और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। आपसी विश्वास, आपसी सम्मान और आपसी संवेदनशीलता हमारे संबंधों की नींव बनी रहनी चाहिए। पीएम मोदी की यह चीन यात्रा ऐसे समय पर हो रही है, जब सारी दुनिया अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प की टैरिफ नीतियों से जूझ रही है। ट्रम्प ने भारत पर रूसी तेल और हथियार खरीद की वजह से 25 फीसदी टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। भारत रूसी तेल का बड़ा खरीददार है।

कनाडा में रिपब्लिक ऑफ खालिस्तान एंबेसी पर विवाद

1.50 लाख डॉलर से बनी बिल्डिंग में अलगाववादी प्रचार, रेडियो प्रमुख ने पीएम कार्नी को भेजा पत्र

जालंधर (एजेंसी)। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के सरे शहर स्थित गुरु नानक सिंघ गुरुद्वारा कॉम्प्लेक्स में %रिपब्लिक ऑफ खालिस्तान% के नाम से एंबेसी ऑफ खालिस्तान का बोर्ड लगाए जाने से नया विवाद खड़ा हो गया है। इस कदम ने न सिर्फ स्थानीय राजनीति, बल्कि भारत-कनाडा संबंधों में भी हलचल मचा दी है। इस पर कड़ा एतराज जताते हुए कनाडा के रेडियो स्टेशन प्रमुख मनिंदर गिल ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी और ब्रिटिश कोलंबिया के प्रांतीय नेताओं को एक सख्त पत्र भेजा है। पत्र में उन्होंने तत्काल जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इसे लेकर भारतीय पक्ष की भी नजर बनी हुई है। अभी तक कनाडा सरकार की ओर से इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। मनिंदर गिल ने अपने पत्र में कहा- यह इमारत मूल रूप से एक सामुदायिक केंद्र के रूप में बनाई गई थी, जिसके लिए ब्रिटिश कोलंबिया सरकार ने 150,000 कनाडाई डॉलर दिए गए थे। भारतीय रुपए में ये 95 लाख रुपए बनते हैं। इस इमारत में हाल ही में इसी सरकारी सहायता से लगभग 1.5

लाख डॉलर की लागत से एक लिफ्ट भी लगाई गई थी। यह बिल्डिंग चैरिटी के तौर पर रजिस्टर्ड है और इसका उद्देश्य न केवल सिख समुदाय बल्कि दुनियाभर के अन्य समुदायों के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध कराना था। अब इस इमारत के बाहर रिपब्लिक ऑफ खालिस्तान और एंबेसी ऑफ खालिस्तान के बोर्ड लगाए गए हैं। गिल का कहना है कि इस तरह का कदम न केवल प्रांतीय अनुदान का दुरुपयोग है बल्कि यह कनाडा सरकार की छवि पर भी सवाल उठाता है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि करदाताओं के पैसों से बनी सामुदायिक संरचना को आतंकवादी या अलगाववादी एजेंडा फैलाने के लिए इस्तेमाल करना अस्वीकार्य है। गिल ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस इमारत का इस्तेमाल खुलेआम खालिस्तानी प्रचार के लिए किया जा रहा है, जो कि कनाडा जैसे लोकतांत्रिक और बहुसांस्कृतिक देश के लिए गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने यह भी कहा कि यह एक रजिस्टर्ड कनाडाई चैरिटी है, जो अब एक सहयोगी देश यानी भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के खिलाफ काम कर रही है।

यूपी में 2027 का गेम चेंज कर देगी पीडीए ‘पाठशाला’

अखिलेश यादव ने खेल दिया बड़ा दांव,संकट में बीजेपी

लखनऊ (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के सरकारी स्कूलों के मर्जर के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने पिछले दिनों पीडीए पाठशाला चलाने का बड़ा ऐलान कर दिया है। लखनऊ के सत्ता के गलियारों में इस पर खासी चर्चा चल रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सपा की पीडीए पाठशाला एक साथ कई मोर्चों पर सरकार और बीजेपी को चुनौती देने में सक्षम है। अब देखना ये है कि सपा इस अभियान को किस तरह आगे ले जाती है और बीजेपी व योगी सरकार क्या करती है। दरअसल प्रदेश में सरकारी स्कूलों के मर्जर को लेकर योगी सरकार ने अभियान शुरू किया तो विपक्ष ने इस पर भारी विरोध शुरू कर दिया। समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे को लोकसभा में भी जोर-शोर से उठाया। इस बीच अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया, «समाजवादी साथी बंद होने वाले स्कूलों के गांव में टीम बनाएं। पढ़े-लिखे नौजवानों और पार्टी के समर्थकों या रिटायर्ड शिक्षकों से मेरा निवेदन है कि वे पीडीए पाठशाला बनाकर बच्चों को पढ़ाने और उनका भविष्य सुधारने का काम करें। हम लोग बच्चों की पढ़ाई रुकने नहीं देंगे। पीडीए पाठशाला चलाकर बच्चों की पढ़ाई कराने का काम करेंगे। अगर स्कूल बंद होते हैं तो समाजवादी लोग गांव-गांव जाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। समाजवादी सरकार बनेगी तो स्कूल पुनः और अच्छे खोले जाएंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पीडीए पाठशाला अखिलेश यादव का स्मार्ट मूव है। वह एक साथ कई समाज के कई हिस्सों को छू रहे हैं। सरकारी प्राइमरी स्कूलों में गरीब पिछड़ा, दलित समाज के बच्चे ही सबसे ज्यादा पढ़ते हैं।



आम लोगों ने भी धर्म के लिए दिए हैं कई बलिदान

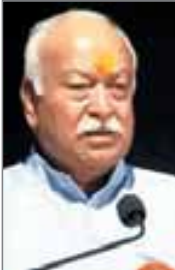
● भागवत बोले-दुनिया को विविधता अपनाने वाले धर्म की जरूरत

संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बताया-जैसे कि अपनाहिंदू धर्म है

नागपुर (एजेंसी)। राष्ट्रीय स्वयंसेवक

संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने बुधवार को कहा कि दुनिया को उस धर्म की जरूरत है जो विविधताओं को अपनाए, जैसे कि हिंदू धर्म। उन्होंने कहा कि धर्म हमें अपनापन और विविधताओं को स्वीकार करना सिखाता है। भागवत ने कहा कि हम विविध हैं, लेकिन अलग नहीं हैं। अंतिम सत्य यह है कि हम अलग दिख सकते हैं, लेकिन वास्तव में हम एक ही हैं। भागवत नागपुर में धर्म जागरण

बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि हर किसी ने फिल्म ‘छावा’ देखी है जो छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित है। केवल महान लोग ही नहीं, आम लोगों ने भी धर्म के लिए बलिदान दिया है। भागवत ने कहा कि धर्म सत्य है और पुण्य कार्य है, जो समाज में शांति बनाए रखने में सहायक होता है। धर्म के मार्ग पर जिम्मेदारी के साथ चलने से व्यक्ति को संकट के समय साहस और रास्ता खोजने का संकल्प मिलता है। संघ प्रमुख ने धर्म के महत्व और समाज में इसकी भूमिका पर बात की।



ट्रम्प धमका रहे,मोदी सामना नहीं कर पा रहे

● राहुल बोले-अडाणी के खिलाफ चल रही अमेरिकी जांच से उनके हाथ बंधे हैं

नई दिल्ली (एजेंसी)। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी, ट्रम्प की धमकियों के सामने खड़े नहीं



हो पा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि अडाणी के खिलाफ अमेरिकी जांच चल रही है। ऐसे में मोदी के हाथ बंधे हुए हैं। मोदी का एए (अडाणी-अंबानी) के साथ क्या संबंध है, यह उजागर हो चुका है। पिछले साल अमेरिका में अडाणी समेत 8 लोगों पर अरबों रुपए की धोखाधड़ी के आरोप लगे थे। अमेरिकी अर्टॉनी ऑफिस आरोप पत्र के मुताबिक, अडाणी ने भारत में प्रोजेक्ट गलत तरीके से हासिल किए थे।

प्रधानमंत्री मोदी ने कर्तव्य भवन का किया उद्घाटन

● इसमें गृह और विदेश समेत सात मंत्रालयों के ऑफिस

24 कॉन्फेंस रूम के साथ 600 कार हो सकेंगी पार्क

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को दिल्ली में कर्तव्य भवन पर कर्तव्य भवन-03 बिल्डिंग का उद्घाटन किया। यह 2019 में शुरू हुई सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है और कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरिएट की 10 में से पहली बिल्डिंग है। कर्तव्य भवन-03 का उद्घाटन सबसे पहले किया गया है। इसे दिल्ली के अलग-अलग जगहों पर स्थित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को एक साथ लाकर उनके बीच बेहतर कोआर्डिनेशन और कामों में तेजी लाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें ग्राउंड फ्लोर सहित 7 फ्लोर हैं। यहां गृह



गैस मंत्रालय, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार और इंटेलीजेंस ब्यूरो के ऑफिस होंगे। यह 1.5 लाख वर्ग मीटर में फैला है।

योजनाओं में सीएम के नाम और फोटो का हो सकेगा इस्तेमाल

● तमिलनाडु सरकार को राहत,सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया हाईकोर्ट का आदेश

चेन्नई (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें तमिलनाडु



सरकार को कल्याणकारी योजनाओं में वर्तमान और पूर्व मुख्यमंत्रियों के नाम व तस्वीरों के उपयोग पर रोक लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए आदेश को निरस्त कर दिया कि यह

याचिका कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई, न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति एनबी अंजरिया की पीठ ने याचिकाकर्ता और अन्नद्रमुक नेता पण्मगुम पर जुर्माना भी लगाया।

दोनों सदनों में बिहार एसआईआर मुद्दे पर हंगामा

नई दिल्ली (एजेंसी)। संसद के मानसून सत्र का आज 13वां दिन था। राज्यसभा और लोकसभा को 7 अगस्त सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। पोर्ट, शिपिंग और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बुधवार को लोकसभा में मर्चेंट शिपिंग बिल, 2024 पेश किया। विपक्ष के हंगामे के बीच बिल पास हुआ। इससे पहले गुरुवार सुबह दोनों सदन शुरू होते ही विपक्ष ने बिहार वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन मामले

पर हंगामा शुरू कर दिया। वहीं, विपक्षी दलों के नेताओं ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला से मांग की है कि नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नर्स बिल 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी (संशोधन) विधेयक, 2025 को संयुक्त संसदीय समिति को भेजा जाए। बीते दिन राज्यसभा में मणिपुर में लागू राष्ट्रपति शासन की अवधि छह महीने और बढ़ाने



का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। वहीं, लोकसभा में गोवा राज्य के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों

के प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन विधेयक, 2024 पारित किया गया। 12 दिनों में अब तक 2 दिन चर्चा हुई 21 जुलाई को शुरू हुए मानसून सत्र के बाद से संसदीय कार्यवाही करीब ठप रही है। बिहार में वोटरों के वेरिफिकेशन मामले पर विपक्षी पार्टियों ने हर दिन विरोध-प्रदर्शन किए। 11 दिनों के दौरान, सिर्फ 28 और 29 जुलाई को सदन में पूरे

दिन की कार्यवाही चली। दोनों दिन, पहलुगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर दोनों सदनों में चर्चा हुई थी। खेल संगठनों और खिलाड़ियों के बेहतर संचालन और पारदर्शिता के लिए लाया गया एक कानून है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत में खेल सब अच्छे तरीके से काम करें और खिलाड़ियों के अधिकारों का ध्यान रखें।

● नहीं चल पाई कार्यवाही,दोनों सदन कल तक स्थगित ● हंगामे के बीच लोकसभा में मर्चेंट शिपिंग बिल पास

कर्ज से तंग युवक ने सुसाइड किया

पिता बोले तकादेदार प्रताड़ित करते थे, जान से मारने की देते थे धमकी

भोपाल (नप्र)। भोपाल के सूखी सेवनिया इलाके में रहने वाले युवक ने सल्वार्स खाकर सुसाइड कर लिया। मृतक के पिता ने तीन लोगों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि बेटे ने महज 5000 रुपए कर्ज लिया था। तीनों आरोपी ब्याज सहित 35 हजार रुपए लौटाने का दबाव बना रहे थे। आए दिन उसे हत्या की धमकी दी जाती थी। इसी के तंग आकर जबान बेटे ने जान दी है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक प्रदीप अहिरवार (30) पिता हरनाम सिंह अहिरवार बालमपुर गांव का रहने वाला था। वह ईंट भट्टे पर काम करता था, इसी के साथ लोडिंग वाहन भी चलाता था। मंगलवार शाम को वह सल्वार्स खाकर घर लौटा। उल्टियां करता देख उससे पूछताछ की तब उसने बताया कि सल्वार्स की तीन गालियां खा ली हैं। तत्काल उसे इमीदिया अस्पताल पहुंचाया गया। इलाज के दौरान बुधवार सुबह उसकी मौत हो गई।

पिता बोले तकादेदारों से छिपता घूम रहा था बेटा- मृतक के पिता हरनाम ने बताया कि शैतान सिंह बंजारा और प्रकाश सिंह बंजारा गांव में रहते हैं। बेटे ने उनसे पांच हजार रुपए उधार लिए थे। जिसे वह लौटा नहीं सका तो आरोपियों ने ब्याज सहित 35 हजार रुपए मांगना शुरू कर दिए। लिहाजा उनके खौफ से बेटे ने घर आना छोड़ दिया, उनसे छिपता घूमता था। पुलिस बोली परिजनों के डिटेल बयानों में होगा खुलासा- पुलिस का कहना है कि मृतक के पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। परिजनों के डिटेल बयानों को भी अभी दर्ज नहीं किया जा सका है। डिटेल बयानों से सुसाइड के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा।

इंस्टा पर युवती से वीडियो कॉल के कई वीडियो- प्रदीप की इंस्टाग्राम आईडी पर एक युवती के साथ वीडियो कॉल पर बात करते हुए उसकी कई वीडियो मौजूद हैं। इन रीलस में अधिकांश सैड सांग भी हैं। लिहाजा पुलिस प्रेम प्रसंग के एंगल पर भी जांच कर रही है।

इंस्टा पर युवती से वीडियो कॉल के कई वीडियो- प्रदीप की इंस्टाग्राम आईडी पर एक युवती के साथ वीडियो कॉल पर बात करते हुए उसकी कई वीडियो मौजूद हैं। इन रीलस में अधिकांश सैड सांग भी हैं। लिहाजा पुलिस प्रेम प्रसंग के एंगल पर भी जांच कर रही है।

एसएफ कॉन्स्टेबल ने बैरक में फांसी लगाई

दो बार पहले भी खुदकुशी की कोशिश कर चुका था, परिजन के सामने मोबाइल का लॉक खोलेगी पुलिस

मुरैना (नप्र)। मुरैना में विशेष सशस्त्र बल (एसएफ) के कॉन्स्टेबल ने बुधवार को बैरक में ही आत्महत्या कर ली। पांचवीं बटालियन में पदस्थ आरक्षक रविन्द्र शर्मा (48) ने कपड़े सुखाने के लोहे के तार से गमछा बांधकर फांसी लगाई। घटना के वक्त बैरक में कोई नहीं था।

प्राथमिक जानकारी के मुताबिक, रविन्द्र शराब की लत से परेशान था। इससे पहले भी दो बार आत्महत्या की कोशिश कर चुका था। रविन्द्र शर्मा ग्वालियर जिले के डबरा तहसील में बरैड़ा गांव का रहने वाला था। 2003 में एसएफ में भर्ती हुआ था। शराब का आदी होने की वजह से वह परिजन से भी ज्यादा मेल-जोल नहीं रखता था।

कमांडेंट बोले- ड्यूटी से अवसर गायब रहता था- एसएफ कमांडेंट रघुवंश सिंह भदौरिया ने बताया कि रविन्द्र को कई बार समझाया गया, लेकिन वह शराब नहीं छोड़ता था। इसी कारण ड्यूटी से भी अवसर गायब रहता था। वहीं, डिटी कमांडेंट कमल मौर्या ने कहा- रविन्द्र फरस्टेशन की वजह से काफी शराब पीता था। हम मामले की जांच कर रहे हैं।

एक महीने पहले हुई थी पोस्टिंग मुरैना एसपी समीर सौरभ ने बताया कि रविन्द्र को एक महीने पहले ही पांचवीं बटालियन में पोस्ट किया गया था। उसका मोबाइल लॉक है, परिजन के आने के बाद उसे खोला जाएगा। एफएसएल टीम ने मौके पर जांच की है।

भोपाल की आदमपुर खंती में आग पर सीपीसीबी की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की, एक्सपर्ट बोले- 80 पेज की रिपोर्ट में स्थिति बहुत खतरनाक

भोपाल (नप्र)। भोपाल की आदमपुर कचरा खंती में आग की घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रहे प्रकरण में मंगलवार को सुनवाई हुई। जिसमें सीपीसीबी (सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड) ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। कोर्ट ने 16 मई की सुनवाई में सीपीसीबी से रिपोर्ट तलब की थी। 80 पेज की रिपोर्ट में सीपीसीबी ने कोर्ट को बहुत कुछ बताया है। प्रकरण में अगली सुनवाई पांच दिन बाद संभावित है।

मामले में भोपाल के पर्यावरणविद् डॉ. सुभाष सी. पांडे ने कहा कि सीपीसीबी की 80 पेज की रिपोर्ट में स्थिति ठीक नहीं बताई गई है। पानी में 100 गुना से ज्यादा आयरन मिला है। यहां का पानी न सिर्फ पीने बल्कि सब्जी और फसलों के पैदावार के लिए भी ठीक नहीं है।

बता दें कि यह मामला नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) से जुड़ा है। पर्यावरणविद् डॉ. पांडे ने आदमपुर खंती में आग लगने की घटनाओं को लेकर एनजीटी में मार्च 2023 में याचिका दाखिल की थी। इस पर 31 जुलाई-23 को नगर निगम पर 1 करोड़ 80 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। एनजीटी के इस आदेश के खिलाफ निगम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। जिस पर 16 मई-25 को सुनवाई हुई थी। इसमें निगम की ओर से जुर्माने की राशि माफ किए



विधानसभा में 6 विधेयक पेश

कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया स्टांप ड्यूटी बढ़ाने के विरोध में नारेबाजी, बोले- जनता पर बोझ बढ़ाया जा रहा

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश विधानसभा का वर्षाकालीन सत्र बुधवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। इससे पहले विधानसभा में बुधवार को 6 विधेयक पेश किए गए। मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान संशोधन विधेयक 2025 समेत 5 विधेयक चर्चा के बाद पारित कर दिए गए। मोटर यान कराधान विधेयक पर चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक बाला बच्चन ने कहा कि भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर संभागों में वाहनों पर ढाई हजार करोड़ के टैक्स बकाया है। सरकार इसे क्यों नहीं वसूल पा रही है। भंवर सिंह शेखावत ने कहा कि आरटीओ दफ्तर एजेंटों के भरोसे चल रहे हैं। लोग टैक्स की बढ़ी हुई राशि नहीं देंगे। जवाब में परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कहा- पहले 4 प्रतिशत पेनल्टी लगती थी जो लंबी दूरी के हिसाब से होती थी। नई व्यवस्था में 4 प्रतिशत पेनल्टी तो लगेगी ही, पुराना बकाया होने पर 4 गुना अधिक राशि भी वसूली जाएगी। बस या अन्य वाहनों में क्षमता से अधिक अधिक लोगों को बिठाने पर 1000 रुपए प्रति सीट पेनल्टी वसूली जाएगी।

कांग्रेस विधायक खाकी वर्दी पहनकर विधानसभा पहुंचे

इससे पहले कांग्रेस विधायक खाकी वर्दी पहनकर विधानसभा पहुंचे। उन्होंने हाथों में तख्ती लेकर पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाया। सरकार से जांच कराने की मांग की।

कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया- एग््रीमेंट और एफिडेविट पर टैक्स बढ़ाए जाने और विधेयक वापस नहीं लिए जाने के विरोध में नेता प्रतिपक्ष समेत कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया।सदन के बाहर विपक्षी विधायकों ने सरकार के फैसले के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

विपक्ष ने सवाल उठाए, मंत्री बोले- संशोधन जनता के हित में है- नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि उपमुख्यमंत्री बताएं कि क्या जो टैक्स लगा रहे हैं, स्टांप ड्यूटी बढ़ा रहे हैं, उस विधेयक को वापस लेंगे या नहीं लेंगे। इसका सीधा जवाब दें। उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने जवाब देते हुए कहा कि जो बढ़ाया है वह सोच-



विजयवर्गीय ने कांग्रेस विधायक बरैया से कहा- मुझे आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है

समाज के कमजोर वर्गों के लिए विधिक सहायता और विधिक सलाह निरसन विधेयक 2025 पर सदन में असहज स्थिति बन गई। संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि विधायक फूल सिंह बरैया द्वारा विषयवस्तु से बाहर वक्तव्य दिया जा रहा है, इसलिए विषय पर बात होनी चाहिए। बरैया ने जवाब में कहा कि इससे दिखता है कि विजयवर्गीय की एससी-एसटी के प्रति प्रजातांत्रिक सोच कैसी है। इस पर मंत्री ने कहा- मुझे आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सात बार से अपने क्षेत्र से निर्वाचित हो रहा हूं।

समझकर बढ़ाया है। एससी-एसटी और ओबीसी के लिए एफिडेविट मुफ्त है। यह संशोधन 11 साल के बाद आए हैं, जो 64 बिंदु में से 12 बिंदु में प्रभावी होंगे। परिवार में संपत्ति विभाजन में प्रॉपर्टी विभाजन पर विधवा भाभी और उसके बच्चों को स्टांप ड्यूटी जमा करने के लिए पहले ज्यादा राशि देनी पड़ती थी, इस पर 5 प्रतिशत स्टांप शुल्क लगता था, जिसे अब परिवार की परिभाषा के मुताबिक फोकस करते हुए 0.5 प्रतिशत ही तय किया गया है। अभी परिवार के सदस्यों पर 0.5 प्रतिशत पीसफुल क्लिनिक का प्रावधान है जो अब विधवा भाभी और उसके बच्चों पर भी लागू होगा।

ऐसे मामले जिनमें कम पंजीयन फीस जमा की गई हो और शासन द्वारा शुल्क वसूली के लिए आदेश जारी किए गए हैं, ऐसे मामले में अब नई धारा जोड़ी गई है। जिसके विरुद्ध अपील भी की जा सकेगी। ऐसे दस्तावेज जिसमें स्टांप शुल्क जमा नहीं किया गया है, उस पर पेनल्टी दो प्रतिशत लगती है, जिसे अब एक प्रतिशत किया जा रहा है। यह संशोधन जनता के हित में है।

- सिंघार बोले- स्टांप ड्यूटी बढ़ाने की जरूरत क्या- नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने चारों विधेयकों पर चर्चा करते हुए कहा कि सदन को नियम-कानून, विधेयक बनाने का

एमपी हाईकोर्ट के स्टे पर एक विक्रम अवॉर्ड होल्ड

● सीएम ने 11 विक्रम और 11 एकलव्य पुरस्कार दिए; एक पर दो पर्वतारोही आमने-सामने



भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश में शिखर खेल अलंकरण और 38वें नेशनल गेम्स 2025 के पदक विजेताओं खिलाड़ियों का सम्मान किया गया। मंगलवार को भोपाल के रविंद्र भवन में सीएम डॉ. मोहन यादव ने 11 विक्रम और 11 एकलव्य पुरस्कार दिए।

इंपर, इंदौर हाईकोर्ट के स्टे के बाद एक विक्रम अवॉर्ड को होल्ड कर दिया गया। छिंदवाड़ा की

भावना डेहरिया को सरकार ने विक्रम अवॉर्ड 2023 के लिए चुना था। भावना के चयन को लेकर पर्वतारोही मधुसूदन पाटीदार ने चुनौती दी थी। पाटीदार ने 2017 में एवरेस्ट फतह किया था।

कोर्ट ने मधुसूदन की याचिका पर सरकार से 7 हफ्ते में जवाब मांगा था। लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। जिसके बाद कोर्ट ने स्टे के आदेश जारी किए। कोर्ट ने कहा कि जब तक उनकी रिप्रेजेंटेशन तय नहीं होगी, तब तक विक्रम अवॉर्ड (स्पेशल एडवेंचर अवॉर्ड) किसी को नहीं दिया जाए। इस मामले में खेल विभाग ने कहा कि नियम अनुसार 5 साल के अंतराल में आवेदन करने वाले ही पात्र होते हैं। नियम अनुसार भावना डेहरिया ही विक्रम अवॉर्ड के लिए पात्र है।

खेल विभाग ने कहा- भावना ही अवॉर्ड के लिए पात्र- खेल एवं युवा कल्याण विभाग के संचालक राकेश गुप्ता ने बताया कि छिंदवाड़ा की भावना डेहरिया को सरकार ने विक्रम अवॉर्ड के लिए चुना था। भावना के चयन को लेकर पर्वतारोही मधुसूदन पाटीदार ने चुनौती दी थी। मधुसूदन ने 2017 में एवरेस्ट फतह किया था। विभागीय नियम के अनुसार 5 वर्ष में आवेदन करने वाले ही अवॉर्ड के लिए पात्र है।

निर्माणाधीन मकान की छत से गिरी मासूम, मौत

पिता ठेकेदार से बात कर रहा था, मां बर्तन धोने में व्यस्त थी तब हुआ हादसा

भोपाल (नप्र)। भोपाल के कोकता में निर्माणाधीन मकान की छत से गिरकर पांच साल की मासूम बच्ची की मौत हो गई। हादसे के समय पिता ठेकेदार से बात कर रहे थे, जबकि मां बर्तन धोने में व्यस्त थी। बच्ची खेलते हुए पहली मंजिल पर पहुंची, यहां बिना मुंडेर की छत से गिरकर घायल हो गई। हादसा सोमवार की शाम साढ़े पांच बजे का है। बुधवार की सुबह सात बजे इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई। बिल्डिंजरिया पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। पीएम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। कामनी बंसल (5) पुत्री श्रवण बंसल राजधानी परिसर कोकता में स्थित निर्माणाधीन मकान में मां-पिता के साथ रहती थी। उसके पिता मिस्त्री का काम करते हैं। परिवार मूल रूप से दमोह का रहने वाला है। रक्षाबंधन की छुट्टी के लिए बच्ची के पिता सोमवार की शाम को घर आए ठेकेदार से बात कर रहे थे।

पिता को पड़ोसियों ने दी मासूम के गिरने की सूचना- मासूम के गिरने के बाद पड़ोसियों ने उसके पिता को हादसे की सूचना दी। इसके बाद पिता ने खुन से लथपथ बच्ची को अस्पताल पहुंचाया। जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।



संपादकीय

धराली की चेतावनी!

उत्तराखंड के उत्तरकाशी ज़िले के धराली गांव में मंगलवार को बादल फटने से खीर गंगा गंदेरे (गहरी खाई या नाला) में अचानक आई बाढ़ और उससे मची तबाही फिर इस बात का संकेत है कि हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ और छेड़छाड़ बंद करें। धराली के साथ पास के हर्षिल में भी ऐसे ही विनाश की चिंताजनक खबर है। धराली में पांच लोगों की मौत की पुष्टि हुई और करीब सौ लोग लापता हैं, जिनमें सेना के 10 जवान भी हैं। हालांकि अपने साथियों के लापता होने के बाद भी वहां मौजूद सैनिकों ने बचाव कार्य में देरी नहीं की। इस बीच स्थानीय प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना मिलकर राहत कार्य में जुटी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मृतकों के प्रति संवेदना जताते हुए पीड़ितों की हर संभव सहायता के आदेश दिए हैं। लेकिन वहां की कठिन भौगोलिक स्थिति और मौसम के कारण बचाव कार्य में लगी एजेंसियों को अपना काम करने में दिक्कत आ रही है। धराली आपदा के जो वीडियो वायरल हुए हैं, वह वाकई डरावने हैं। जिसमें कई मकान और होटलों प्रलयकारी बाढ़ अपने साथ पल में बहा ले गई। ज्यादातर नुकसान किनारे की बस्तियों में हुआ है। गौरतलब है कि धराली, गंगोत्री धाम से लगभग 20 किलोमीटर पहले स्थित एक प्रमुख पड़ाव है, जहां हर साल चारधाम यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु रुकते हैं। वहां इस हादसे के बाद स्थानीय लोगों की पीड़ा का सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। लोगों का यह भी कहना है कि उन्हें ऐसी किसी आपदा की कोई चेतावनी प्रशासन ने नहीं दी थी। धराली के लोग एक स्थानीय पूजा समारोह में व्यस्त थे और यह हादसा हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जहां हादसा हुआ, वहां बहुत बड़े-बड़े होटल थे। अब उनकी छत तक नहीं दिख रही। धराली का पूरा मार्केट खत्म हो गया। एक बहुत बड़ा मंदिर भी ध्वस्त हो गया है। लोगों की आस्था का केन्द्र कल्प केदार मंदिर भी नहीं दिख रहा है। बताया जाता है कि धराली में बादल फटने के कारण भूस्खलन हुआ और एक पहाड़ धंस कर कयामत की धारा में बदल गया। मौसम विभाग के मुताबिक, एक घंटे में 10 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा भारी बारिश, छोटे इलाके (एक से दस किलोमीटर) में हो जाए तो उस घटना को बादल फटना कहते हैं। कभी-कभी एक जगह पर एक से ज्यादा बादल फट सकते हैं। ऐसी स्थिति में जान-माल का ज्यादा नुकसान होता है जैसा उत्तराखंड में साल 2013 में हुआ था, लेकिन हर भारी बारिश बादल फटना नहीं होती। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मानसून और मानसून के कुछ समय पहले (प्री-मानसून) इस तरह की घटना ज्यादा होती हैं। बादल फटने की घटनाएं एक से दस किलोमीटर की दूरी में छोटे पैमाने पर हुए मौसमी बदलाव की वजह से होती हैं। इस वजह से इनका पूर्वानुमान लगाना मुश्किल होता है। ऐसे मौसमी बदलावों को बताने या मॉनिटर करने के लिए या तो बादल फटने की आशंका वाले इलाकों में घने रडार नेटवर्क की जरूरत होती है, या फिर बहुत हाई रेजोल्यूशन वाले मौसम पूर्वानुमान मॉडल चाहिए जो इतनी छोटी स्केल की घटनाओं को पकड़ सकें। हमारे यहां इसकी कमी है। इसका कारण यह है कि बादल फटने और उससे हुई तबाही के चलते तात्कालिक तौर पर चिंताएं जाती हैं। बाद में सब भुला दिया जाता है। हिमालय में स्थिति तो और भयावह है। पेड़ लगातर कट रहे हैं और प्रकृति अनावृत होती जा रही है। परिणामस्वरूप मौसम चक्र बदल रहा है। और इसके लिए सर्वाधिक जिम्मेदार मानव गतिविधियां हैं। देवभूमि में भी जिस तरह अंधाधुंध पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है, निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, उन सबका नतीजा ऐसे भयंकर हादसे हैं।

जिनेवा देगा प्लास्टिक प्रदूषण से मुक्ति की राह?

नजरिया

राजकुमार सिन्हा

लेखक पर्यावरण के जानकार हैं।



स्विट्जरलैंड के जिनेवा में 5 से 14 अगस्त तक प्लास्टिक संधि के लिए अन्तर्राष्ट्रीय वार्ता समिति के प्रतिनिधि मंडल अंतिम बैठक के लिए एकत्रित हुए हैं। जहां प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय कानूनी रूप से बंधनकारी (आईएलबीआई) समझौता पर अंतिम दौर की बातचीत होगी। इसके पहले मई 2022 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा ने समुद्री पर्यावरण सहित प्लास्टिक प्रदूषण पर एक अंतरराष्ट्रीय, कानूनी रूप से बाध्यकारी उपाय विकसित करने के लिए प्रस्ताव पारित किया था। तब से अबतक पांच दौर की बातचीत पूर्ण हो चुकी है। अंतिम दौर की बातचीत अगस्त में होने जा रही है। जिसमें मुख्यतः प्लास्टिक उत्पादों के पूरे जीवन काल में प्राथमिक पॉलिमर उत्पादन से लेकर निपटान तक को ध्यान में रखें जाने की बात होगी। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार, प्लास्टिक की माँग सन् 2000 के बाद से लगभग दोगुनी हो गई है। एक हालिया अध्ययन के अनुसार, 2022 में फीडस्टॉक सहित 436.66 मिलियन टन पॉलिमर और प्लास्टिक का व्यापार हुआ, जिसमें अंतिम प्लास्टिक उत्पादों की मात्रा 111 मिलियन टन थी। आज, 99व प्लास्टिक जीवाश्म ईंधन से बनता है। जीवाश्म ईंधनों को परिष्कृत करके मोनोमर्स (निर्माण खंड) और फिर पॉलिमर में संसाधित किया जाता है, और उत्पादन के विभिन्न चरणों में मध्यवर्ती पदार्थ भरने की प्रणालियों को प्राथमिकता देने और मानव अधिकारों के संरक्षण का भी आह्वान किया है। कहा गया है कि प्लास्टिक और खतरनाक अपशिष्ट के उत्पादन में प्रयुक्त खतरनाक रसायनों पर बासेल, रॉटरडैम और स्टॉकहोम द्वारा नियंत्रण किया जाता है। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) द्वारा शासित होता है, और प्रस्तावित आईएलबीआई के प्रावधान डब्ल्यूटीओ समझौते के विपरीत होंगे। इससे विकासशील देश और वे देश जो पॉलिमर व्यापार पर निर्भर हैं, व्यापार पर अकुश लगाने से प्रभावित होंगे। इधर पर्यावरण पर 20वें अफ्रीकी मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (एएमसीईएन-20) ने वैश्विक प्लास्टिक संधि का समर्थन करने की प्रतिबद्धता जताई है, तथा प्लास्टिक प्रदूषण पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनी रूप से बाध्यकारी साधन विकसित करने के लिए अंतर-सरकारी वार्ता समिति (आईएनसी) के साथ महाद्वीप की सहभागिता की आवश्यकता की पुष्टि की है। 18 जुलाई को नैरोबी में संपन्न हुई इस बैठक में स्वीकार किया गया कि अफ्रीका अपनी प्राकृतिक पूंजी की रक्षा के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है, जिसमें विविध परिस्थितिकी तंत्र, परिदृश्य, वायु,

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार, प्लास्टिक की माँग सन् 2000 के बाद से लगभग दोगुनी हो गई है। एक हालिया अध्ययन के सहित 436.66 मिलियन टन पॉलिमर और प्लास्टिक का व्यापार हुआ, जिसमें अंतिम प्लास्टिक उत्पादों की मात्रा 111 मिलियन टन थी। आज, 99 प्रतिशत प्लास्टिक जीवाश्म ईंधन से बनता है। जीवाश्म ईंधनों को परिष्कृत करके मोनोमर्स (निर्माण खंड) और फिर पॉलिमर में संसाधित किया जाता है, और उत्पादन के विभिन्न चरणों में मध्यवर्ती पदार्थ भरने की प्रणालियों को प्राथमिकता देने और मानव अधिकारों के संरक्षण का भी आह्वान किया है। कहा गया है कि प्लास्टिक और खतरनाक अपशिष्ट के उत्पादन में प्रयुक्त खतरनाक रसायनों पर बासेल, रॉटरडैम और स्टॉकहोम द्वारा नियंत्रण किया जाता है। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) द्वारा शासित होता है, और प्रस्तावित आईएलबीआई के प्रावधान डब्ल्यूटीओ समझौते के विपरीत होंगे। इससे विकासशील देश और वे देश जो पॉलिमर व्यापार पर निर्भर हैं, व्यापार पर अकुश लगाने से प्रभावित होंगे। इधर पर्यावरण पर 20वें अफ्रीकी मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (एएमसीईएन-20) ने वैश्विक प्लास्टिक संधि का समर्थन करने की प्रतिबद्धता जताई है, तथा प्लास्टिक प्रदूषण पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनी रूप से बाध्यकारी साधन विकसित करने के लिए अंतर-सरकारी वार्ता समिति (आईएनसी) के साथ महाद्वीप की सहभागिता की आवश्यकता की पुष्टि की है। 18 जुलाई को नैरोबी में संपन्न हुई इस बैठक में स्वीकार किया गया कि अफ्रीका अपनी प्राकृतिक पूंजी की रक्षा के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है, जिसमें विविध परिस्थितिकी तंत्र, परिदृश्य, वायु,

समुद्र जैव विविधता से लेकर विशाल खनिज संपदा, मीठे पानी और समुद्री संसाधन शामिल हैं। इस कार्यक्रम में सदस्य देशों से पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण को अपनाने तथा समुदायों, महिलाओं और युवाओं को शामिल करने और उन्हें सशक्त बनाने का आह्वान किया गया, ताकि पर्यावरणीय संरक्षण को बढ़ावा दिया जा सके और ऐसे भावी नेताओं को तैयार किया जा सके जो टिकाऊ प्रथाओं को प्राथमिकता दें। प्लास्टिक प्रदूषण दुनिया के हर कोने में फैल चुका है, हमारे पीने के पानी, हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन और हमारे शरीर में घुल रहा है। प्लास्टिक के अंधाधुंध उपयोग के कारण, 4,200 से ज्यादा चिंताजनक प्लास्टिक रसायन हमारे शरीर, भोजन और पारिस्थितिकी तंत्र को दूषित करते हैं। माइक्रोप्लास्टिक मानव रक्त, प्लेसेंटा और अंगों में घुस गया है, जबकि उत्पादन, भस्मीकरण और पुनर्चक्रण से निकलने वाला विषाक उत्सर्जन समुदायों के लिए जुहर बन रहा है। एक नए वैश्विक अध्ययन से पता चला है कि 2018 में दुनियाभर में दिल की बीमारी से हुई 3,56,000 से ज्यादा मौतों का संबंध प्लास्टिक उत्पादों में इस्तेमाल होने वाले एक विशेष रसायन 'डाइ-2-एथाइलहेक्सिल फ्थैलेट (डीईएचपी)' से था। यह रसायन प्लास्टिक को लचीला बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसे मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा माना जा रहा है। सन् 2000 और 2019 के बीच, लगभग 3 करोड़ टन प्लास्टिक समुद्री वातावरण में जमा हो गया है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि 2050 तक, समुद्रों में मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक हो सकता है। प्लास्टिक प्रदूषण जलवायु परिवर्तन का संकेत, प्रकृति, भूमि और जैव विविधता का ह्रास और प्रदूषण एवं अपशिष्ट का संकेत पैदा करता है। वैश्विक स्तर पर, अनुमानतः हर साल 1.1 करोड़ टन प्लास्टिक कचरा जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में रिसता है, जबकि कृषि उत्पादों में प्लास्टिक के

उपयोग के कारण, मल और लैंडफिल से मिट्टी में सूक्ष्म प्लास्टिक जमा हो जाता है। प्लास्टिक प्रदूषण की वार्षिक सामाजिक और पर्यावरणीय लागत 300 अरब अमेरिकी डॉलर से 600 अरब अमेरिकी डॉलर के बीच है। भारत में कुल प्लास्टिक का 62 प्रतिशत पैकेजिंग के लिए उपयोग किया जाता है - जो वैश्विक औसत 40 प्रतिशत से कहीं अधिक है। प्लास्टिक पैकेजिंग की खपत सालाना 8 से 9 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है।अगर मौजूदा रुझान जारी रहे, तो भारत में प्लास्टिक पैकेजिंग की खपत लगभग दोगुनी हो जाएगी। सन् 2022 में 1.1 करोड़ टन से बढ़कर 2030 तक 2 करोड़ टन हो जाएगी। ब्रिटेन के लीड्स विश्व विद्यालय के शोधकर्ताओं के अनुसार दुनिया में भारत प्लास्टिक कचरे का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। यहां हर साल 1.02 करोड़ टन प्लास्टिक कचरा पैदा होता है। जीवनचक्र दृष्टिकोणों के लिए वैश्विक प्रयासों के बावजूद, पेट्रोकेमिकल उद्योग में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी, भारत, संधि के दायरे को केवल अनुप्रवाह उपायों तक ही सीमित रखता है। वह मूल कारण का समाधान करने में विफल रहता है, जो कि प्लास्टिक का अनियमित उत्पादन है (जिसमें से 50 प्रतिशत एकल-उपयोग वाला है), जो अपशिष्ट प्रणालियों पर अत्यधिक बोझ डालता है और उत्पादन से लेकर उपयोग और अपशिष्ट के रूप में निपटान तक, प्रदूषण और जन स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा करता है। इससे भी बदतर, अपशिष्ट से ऊर्जा भस्मीकरण, जो विषाक पदार्थों और सूक्ष्म प्लास्टिक को छोड़ता है, भारत को इस दिशा में ठोस प्रयास करने की जिम्मेदारी है। भारत के नागरिक अपने प्रतिनिधिमंडल से आग्रह करते हैं कि इस हद पर जाने वाली में मानव स्वास्थ्य और अपस्ट्रीम समाधानों पर केन्द्रित एक मजबूत वैश्विक प्लास्टिक संधि का समर्थन करें। जबकि प्लास्टिक पैकेजिंग, डिजाइन और सामग्री के उपयोग पर जीवनचक्र आकलन के आधार पर स्पष्ट लागू करने योग्य दिशानिर्देशों की तत्काल आवश्यकता है।

पेड़ों की कटाई का नया आयाम सोलर पावर प्लांट योजनाएं

पर्यावरण

ब्रजेश कानूनगो

लेखक स्तंभाकार हैं।



भारत में कई बड़ी विकास परियोजनाओं के लिए पेड़ों को बड़ी संख्या में काटा जाता रहा है। आधुनिक जीवन की सुविधाओं के लिए भी कई योजनाएं बनती रहीं हैं जिनके कारण पेड़ों की व्यापक रूप से कटाई की गई है। प्रमुख रूप से अनेक बांध और जलाशय परियोजनाओं का उल्लेख किया जा सकता है, कई बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं जिनके लिए वनों को कटाई हुई है। चाहे वह सतलुज नदी पर स्थित, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में फैली हुई भाखड़ा नंगल परियोजना हो, उड़ीसा में महानदी पर हीराकुंड बांध परियोजना हो, नर्मदा नदी पर स्थित, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में फैली हुई सरदार सरोवर परियोजना रही हो। इसके अलावा सड़कों और रेलवे लाइनों के निर्माण के लिए भी पेड़ों को काटा जाता रहा है। शहरों के विस्तार और विकास के कारण पेड़ों की संख्या घटती चली जाती है ताकि नए घर, सड़कें, और अन्य बुनियादी ढांचे बनाए जा सकें। उद्योगों की निर्माण परियोजनाओं तथा खनन और उखनन परियोजनाओं में खनिज संसाधनों की खोज और उनके उपयोग के लिए वनों को व्यापक रूप से समाप्त किया जाता रहा है। इन परियोजनाओं के कारण वनों की कटाई और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ना है, इसलिए इन परियोजनाओं को लेकर पर्यावरण कार्यकर्ताओं, जागरूक नागरिकों, बुद्धिजीवियों सहित किसानों और उन क्षेत्रों के प्रभावित होने वाले ग्रामीणों द्वारा विरोध और प्रतिरोध में आवाजें उठाई जाती रहीं हैं। जिनके कारण विकास के नकारात्मक पक्ष को कम

किए जाने में मदद भी मिली है। बहुत लोगों को आज भी 1970 के दशक के पर्यावरण कार्यकर्ता सुंदरलाल बहुगुणा जी की प्रेरणा में हुए चिपको आंदोलन की स्मृति अवश्य होगी जिसमें उत्तराखंड में वनों की कटाई के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन हुआ था तथा महिलाओं ने पेड़ों को काटने से रोकने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस आंदोलन के परिणामस्वरूप सरकार ने हिमालयी क्षेत्रों में 15 वर्षों के लिए वनों की कटाई पर रोक लगा दी थी। हाल ही की बात करें तो महाराष्ट्र राज्य में आरे कॉलोनी में मेट्रो कार शेड परियोजना एक बहुचर्चित और विवादित मुद्दा है, जिसमें पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन बनाने की चुनौती खड़ी हुई। इस परियोजना के तहत मुंबई मेट्रो के लिए कार शेड बनाने के लिए आरे कॉलोनी में पेड़ों की कटाई की जा रही थी, जिसका व्यापक विरोध हुआ। मुंबई मेट्रो की लाइन-3 के लिए कार शेड बनाने के लिए आरे कॉलोनी में जमीन का उपयोग करने की योजना थी। जिसका उद्देश्य मुंबई में सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाना और यातायात की समस्या को कम करना था। आरे कॉलोनी में पेड़ों की कटाई के खिलाफ व्यापक विरोध हुआ, जिसमें पर्यावरणविद, सामाजिक कार्यकर्ता और बॉलीवुड हस्तियों ने भाग लिया। उनका तर्क था कि आरे कॉलोनी एक हरित क्षेत्र है और पेड़ों की कटाई से पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। दूसरी ओर, परियोजना के समर्थकों का तर्क था कि मेट्रो परियोजना से मुंबई के लोगों को बेहतर परिवहन सुविधा मिलेगी और शहर के विकास में मदद मिलेगी। इस मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय में सुनवाई

हुई, जिसमें न्यायालय ने मुंबई मेट्रो को आरे कॉलोनी में 84 पेड़ काटने की अनुमति दी। हालांकि, महाराष्ट्र सरकार ने बाद में इस परियोजना को कांजुरमार्ग में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। सरकार के इस निर्णय से परियोजना की लागत में वृद्धि होगी और परियोजना के पूरा होने में देरी हो सकती है। कहा जा रहा है कि इससे पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम करने में मदद मिलेगी हाल ही में इन सबसे हटकर राजस्थान में सोलर पावर प्लांट और सौर्य ऊर्जा के विकास को लेकर एक नया मुद्दा गर्म होता गया है। दरअसल राजस्थान में सोलर पावर प्लांट पार्क स्थापित करने के लिए पेड़ों की कटाई की घटनाएं सामने आई हैं। जोधपुर जिले के फाल्दी तहसील में सोलर प्लांट लगाने के लिए लगभग 10,000 खेजड़ी के पेड़ काट दिए गए थे, जिस पर विश्वभरी समाज ने कड़ा विरोध जताया और आंदोलन की चेतावनी दी। राजस्थान में सौर ऊर्जा संयंत्र योजनाओं के अंतर्गत पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत राजस्थान में 5 लाख घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य है। जानकारी के अनुसार योजना में आवेदन शुल्क, अमानत राशि और मीटर चार्ज नहीं लिया जाएगा, और 3 किलोवाट तक के सोलर पैनल पर 78,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। इसी तरह सौर कृषि आजीविका योजना में किसानों को अपनी बंजर भूमि पर सोलर प्लांट लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। योजना में 30 प्रतिशत की सब्सिडी सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। कुसुम सोलर योजना के अंतर्गत किसानों को सोलर पंप सेट्स और सोलर

प्लांट्स की स्थापना के लिए सब्सिडी और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। योजना में 7.5 एचपी या उससे कम की क्षमता वाले सोलर पंप सेट्स पर 60 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाती है। इन योजनाओं का उद्देश्य राजस्थान में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना और ऊर्जा आत्मनिर्भरता को बढ़ाना है। विशेषज्ञों का मानना ​​है कि सोलर प्लांट्स के कारण कई पर्यावरणीय संकेत संभावित हैं जिनसे इको सिस्टम प्रभावित होता है। सोलर प्लांट्स के लिए बड़े क्षेत्रों में भूमि की आवश्यकता होती है, जिससे वनों की कटाई और भूमि उपयोग में परिवर्तन होता है। सोलर प्लांट्स के निर्माण और संचालन से जैव विविधता को नुकसान पहुंच सकता है, खासकर यदि प्लांट्स संवेदशील या संरक्षित क्षेत्रों में स्थित हों। सोलर प्लांट्स के निर्माण और संचालन में जल की आवश्यकता होती है, जिससे जल संसाधनों पर दबाव पड़ सकता है। सोलर प्लांट्स के निर्माण से मिट्टी का क्षरण हो सकता है, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता और उर्वरता प्रभावित होती है। सोलर प्लांट्स के पैनल्स और अन्य संरचनाओं से पक्षियों और अन्य जीवों की मृत्यु हो सकती है, खासकर यदि प्लांट्स पक्षियों के प्रवास मार्ग में स्थित हों।

देश के एक प्रमुख अखबार की हाल ही की रिपोर्ट से पता चलता है कि सोलर प्लांट के जुनून से राजस्थान में इको सिस्टम के तबाह होने की आशंका बलवती हुई है। अखबार के अनुसार बीकानेर से बाड़मेर तक के चार जिलों में अब तक 26 लाख पेड़ काटे जा चुके हैं और 38 लाख और काटे जाएंगे। लोगों का कहना है कि केवल बंजर जमीनों पर ही प्लांट स्थापित किए जाएं जबकि शासन प्रशासन की ओर से आश्वासन दिया जा रहा है कि कम से कम वृक्ष काटे जाएंगे और वृक्षों को अन्य स्थानों पर शिफार करने का भी कार्य होगा। राज्य वृक्ष खेजड़ी को काटने पर बड़ा जुनून वसूला जाएगा। आगे देखने की बात यह होगी कि किन उपायों को अपनाकर सोलर प्लांट्स के वृहद अभियान के तहत पर्यावरणीय दुष्प्रभावों को कम किया जाएगा और इको सिस्टम को रक्षा की जा सक्गी। प्रतीक्षा करें!

कटाक्ष

डॉ. हरि जोशी

लेखक व्यंग्यकार हैं।



अमेरिका के किसी मार्गदर्शक ने युधिष्ठिर को कुत्ते के साथ देख लिया होगा, जिसके साथ स्वर्ग की यात्रा युधिष्ठिर ने की थी। इसीलिये शायद अमेरिका में घर-घर कुत्ता रखने की प्रथा आ गई। कुत्ता प्रत्येक परिवार का एक एवईसिव या आसंजक हो गया है। वैसे तो भारत में भी कुत्तों के संवेदशील या संरक्षित क्षेत्रों में स्थित हों। सोलर प्लांट्स के निर्माण और संचालन में जल की आवश्यकता होती है, जिससे जल संसाधनों पर दबाव पड़ सकता है। सोलर प्लांट्स के निर्माण से मिट्टी का क्षरण हो सकता है, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता और उर्वरता प्रभावित होती है। सोलर प्लांट्स के पैनल्स और अन्य संरचनाओं से पक्षियों और अन्य जीवों की मृत्यु हो सकती है, खासकर यदि प्लांट्स पक्षियों के प्रवास मार्ग में स्थित हों। देश के एक प्रमुख अखबार की हाल ही की रिपोर्ट से पता चलता है कि सोलर प्लांट के जुनून से राजस्थान में इको सिस्टम के तबाह होने की आशंका बलवती हुई है। अखबार के अनुसार बीकानेर से बाड़मेर तक के चार जिलों में अब तक 26 लाख पेड़ काटे जा चुके हैं और 38 लाख और काटे जाएंगे। लोगों का कहना है कि केवल बंजर जमीनों पर ही प्लांट स्थापित किए जाएं जबकि शासन प्रशासन की ओर से आश्वासन दिया जा रहा है कि कम से कम वृक्ष काटे जाएंगे और वृक्षों को अन्य स्थानों पर शिफार करने का भी कार्य होगा। राज्य वृक्ष खेजड़ी को काटने पर बड़ा जुनून वसूला जाएगा। आगे देखने की बात यह होगी कि किन उपायों को अपनाकर सोलर प्लांट्स के वृहद अभियान के तहत पर्यावरणीय दुष्प्रभावों को कम किया जाएगा और इको सिस्टम को रक्षा की जा सक्गी। प्रतीक्षा करें!

युधिष्ठिर के अनुगामी

है, कोई 14-15 साल होगी। अच्छा तो अमेरिका में कुत्तों में भी छोटी जाति और बड़ी जाति होती है? मैंने अगला प्रश्न किया- कुत्तों में भी जाति प्रथा होती है? वह बोले -छोटी जाति के सदस्य अधिक जीते हैं, बड़ी नस्ल वालों की उम्र कम होती है। मैंने मन ही मन सोचा यहाँ तो 15-16 साल की उम्र के लड़कें लड़कियां, ब्रॉय फ्रेंड या गर्ल फ्रेंड बनकर साथ-साथ घूमने लगते हैं? ताकि अठारह के होते-होते वे पैतृक घर से दूर हो जाएँ, अपना अलग घर बनायें। 18 साल की उम्र के बाद तो, बेटे-बेटी भी बाप के लिए बोझ सరిखे माने जाते हैं। माता-पिता भी उन्हें घर छोड़ने को पहले प्रेरित और बाद में मजबूर कर देते हैं। मैंने पूछा अरे उसे आप अकेली बाहर छोड़ आये? मैंने सोचा- अमेरिका में बच्चियों के माँ बन जाने के याने चाइल्ड मंदर के प्रकरण सर्वाधिक हैं इसीलिये यह सज्जन चिंतित होंगे। मैंने पूछ-भीतर ले आते तो वह भी कॉर्पोरी लेली? कुछ खा लेती? उत्तर मिल- -वह हमारा भोजन नहीं करती। उसके लिए बाज़ार से बीफ मिश्रित पैकड फुड लाना पड़ता है। मैं समझ गया यदि बच्चे लाइ प्यार में पले बड़े हुए हों तो जो कुछवे खाने को मांगते हैं वह उन्हें खिलाया जाता है। लाइ में पली होगी? मैंने मन ही मन सोचा।

स्वामी, सुबह सवेंरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धिविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबन्धु पर्सिस्, प्रेस कॉम्पलेक्स, जौन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक

उमेश त्रिवेदी

कार्यकारी प्रधान संपादक

अजय बोकिल्

संपादक (मध्यप्रदेश)

विनोद तिवारी

वरिष्ठ संपादक

पंकज शुक्ला

प्रबंध संपादक

अरुण पटेल

(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)

RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,

Ph. No. 0755-2422692, 4059111

Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

लंय

विजी श्रीवास्तव

लेखक व्यंग्यकार हैं।



दुनिया भर में इन दिनों कुछ 'तैलांद' माहौल बना हुआ है। खनिज तेल की आवा-जाही के चौराहे पर अमरीका चालान काटने को बेताब दरोगा बनकर डटा हुआ है। उधर देश में चुनावी तापमान बढ़ते ही, बिहार की कड़ुही में जातिवादी पूर्णिया तली जाने लगी है। वहीं बीमार, अरे नहीं तिमारादार महकमे की ओर से आया नया 'फरमान-ए-सेहत' भी कम अचरज वाला नहीं है। हैल्थ डिपार्टमेंट का हुकुमनामा गौर तलब है- समोसे, जलेबी और वड़ा-पाव जैसे तले-भुने और मीठे खाद्य पदार्थों पर तेल और शर्करा की मात्रा के बोर्ड लगाए जाएं। फिलहाल ये निर्देश सिर्फ सरकारी कैटीनों और कैफे-टेरेरियाओं तक सीमित हैं, लेकिन हैल्थेट की तरह सभी के सर कब चढ़ा दिया जाएगा, कला नवीं जा सकता। हमारे लोकप्रिय राष्ट्रप्यार्थी नरेंद्र - समोसा, जलेबी, वड़ा-पाव अब कटघरे में हैं। बचपन की यादों में लिपटी छल्लेदार जलेबी अब कैलौरी चार्ट में फंस चुकी है। समोसा अब स्वाद का प्रतीक नहीं, ट्राइलिसराइड का मुजमिम बन गया है। मुंबई की आत्मा वड़ा-पाव, अब फैट-फ्री बॉडी के रकीबों में शुमार किया

तेल, तेल की धार और फैट-फ्री आम आदमी

जाएगा। अब हम खाने की लज्जत नहीं, कैलौरी गिनने के लिए कैलकुलेटर लेकर बैठेंगे। जलेबी-समोसे का हिसाब करने से पहले हमें अपराध भाव से अपने जीवन के फैट प्रतिशत का हिसाब गिनना होगा। बताइये! समोसे में तेल और जलेबी में मिठास बताना ऐसा नहीं है क्या जैसे नहकर निकलते ही घोषणा करनी पड़े कि मेरे शरीर में अभी 1.2 लीटर पानी है, जिसमें 0.8 लीटर कलौरीन मिश्रित है। जानकार बताते हैं कि रोजाना प्रति व्यक्ति 25 ग्राम चीनी और 30 ग्राम तेल पर्याप्त है। पर कोई ये क्यों नहीं बताता कि कितने ग्राम अपमान सहना उचित है? कितने रमपलत आंसू पीना सेहत के लिए सुरक्षित है? अच्छा होता किसी दिन हर मुसीबत, हर भूख, हर अन्याय के लिए भी बोर्ड लग पाते-यहां पीड़ा की डेली लिमिटेड ओवरडोज हो चुकी है। अभी तक सूची में शामिल समोसे और जलेबी की बात ही कानों तक पहुंची है। इसमें चाशनी में लबरेज गुलाब जामुन और तेल में विस्फुरते भजियों को शामिल किया गया है या नहीं, पता नहीं। हो सकता है हमारे जोशीले हैल्थ इन्स्पेक्टर किसी दिन

आदेशों के पालन में मंदिरों में जाकर डेरा डाल दें कि अमुक देवता, जिस पर तेल चढ़ाया जा रहा है, उनके लिपिड प्रोफाइल की घोषणा करो। सरकारें चाहती हैं कि आदमी फैट फ्री हो। लेकिन उन्हें पता ही नहीं चलता कि आम आदमी का तेल इस कदर निकला जा रहा है कि लोग तेजी से पेट फ्री हो रहे हैं। तेल की घानी में पिरेज जाने वाले दिहाड़ी मजदूर, छोटे मोटे काम धंधे कर परिवार का पेट पालने वाले लोग, गले में डिग्री लटकाए नौकरी की तलाश में चम्पल चटकाते युवा और बिन दहेज की शादी के लिए दुनिया भर की खाक छनते लड़की के पिता का तेल निचुड़ा हुआ है। किसान बेचारा सरसों, सोयाबीन, तिल और सरसों जैसी तेल वाली फसलों उगा कर भी अपना तेल निकलवाता रहता है। सिर्फ नेता ही हैं जो पी चुपड़े हैं। उनके बयानों में फुल क्रीम पॉलिटेक्नल पैकेज होता है, उनकी मुस्कान में मक्खन की रसैन्थता और वार्दों में चाशनी की चिपचिचाहट। चुनाव के समय उनका मिठास प्रतिशत उच्चतम होता है। चुनाव जीतते ही वे शुगर फ्री हो जाते हैं। वे हर पांच साल में जनता की उम्मीदों को कुलतते हैं। उनके अंदर का ऑइल परसेंट तब तक शून्य रहता है, जब तक कि वे चुनाव प्रचार के लिए नहीं घूमते। चुनावों से पहले वे

संवेदना शून्य होते हैं। चुनावों के बाद वे जन साधारण के प्रति श्रवणीयता शून्य हो जाते हैं। फिर लम्बे समय तक वे शर्म शून्य हो जाते हैं। हैल्थ डिपार्टमेंट की रिपोर्ट बताती है कि साल 2021 में लगभग 18 करोड़ लोग अधिक वजन या मोटापे से ग्रस्त थे और 2050 तक 44.9 करोड़ हो जाएंगे। रिपोर्ट थोड़ा और खुलासा कर सकती तो पता पड़ जाता कि इन मोटे आसामियों में कौन कौन शामिल हैं। कहने की जरूरत ही नहीं होती कि शोषण से ही पोषण होता है। पर सवाल यह भी है कि जब पेट, हृदय और डाइबिटीज के मरीज इस तादात में बढ़ते जाना है तो हम क्या खाली गिनती लगाने के लिए हैं। हमारे देश में कार्यक्रमों की सफलता बोर्ड, पोस्टर, बैनर लगाने और विज्ञापन देने तक ही है। बाकी सब लाइलाज है। ज्यादा वकत नहीं है कि हमारे देश में हर आदमी के माथे पर स्कैनर चलेगा जिसमें उसके अंदर का तेल प्रतिशत और मिठास की मात्रा प्रदर्शित की जाएगी। तब हर आदमी सुबह उठकर शीशे में खुद से पुछेगा- मेरे अंदर कितना तेल बचा है, मेरी आत्मा कितनी तली हुई है, मैं शुगर-फ्री हूँ या इस समाज में एक फ्रीकी सी हैसियत लिए खस्ता होतूँ?

उत्तराखंड में जल-प्रलय
 प्रमोद भार्गव
 लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

भगवान भोले नाथ का गुस्सा, प्रतीक रूप में मौत के तांडव नृत्य में फूटता है। देवभूमि उत्तराखंड में शिव के इस तांडव नृत्य का सिलसिला केदारनाथ में 2013 में आई प्राकृतिक आपदा के बाद अभी भी जारी है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले की खीर गंगा नदी और धराली में बादल फटने और हरिशिल के तेल गाड़नाले में बाढ़ आने से बड़ी तबाही हुई है। इन प्राकृतिक आपदाओं को हमें इसी गुस्से के प्रतीक रूप में देखने की जरूरत है। धराली में तो 50 से ज्यादा घर, 30 हॉटल और 30 होमस्टे मलबे में बदल गए। जो खीर नदी 10 मी. चौड़ी थी, वह जल प्रवाह से 39 मी. चौड़ी हो गई। अतएव जो भी सामने पड़ा उसे लीलती चली गई। प्रशासन चार लोगों की मौत और 100 से अधिक लोगों के लापता होना बता रहा है। लेकिन हिमालय के बीचोंबीच बसा खुबसूरत धराली गांव में सैलाब नीचे उतरते हुए दिखा, उससे लगता है, मौतें कहीं अधिक हुई हैं। प्रलय इतनी तीव्रता से आया की उसकी कान के पदें फाड़ देने वाली गर्जना सुनने के बाद लोगों को बचने का समय ही नहीं मिल पाया। अब धराली मलबे में दफन हैं।

इस भूक्षेत्र के गर्भ में समाई प्राकृतिक संपदा के दोहन से उत्तराखंड विकास की अग्रिम पांते में आ खड़ा हुआ था, वह विकास भीतर से कितना खोखला था, यहइस क्षेत्र में निरंतर आ रही इस आपदाओं से पता चलता है। बारिश, बाढ़, भूस्खलन, बर्फ की चट्टानों का टूटना और बदलों का फटना, अनायास या संयोग नहीं है, बल्कि विकास के बहाने पर्यावरण विनास की जो पृष्ठभूमि रची गई, उसका परिणाम है। तबाही के इस कहर से यह भी साफ हो गया है कि आजादी के 78 साल बाद भी हमारा न तो प्राकृतिक आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आपदा से निपटने में सक्षम है और न ही मौसम विभाग आपदा की सटीक भविष्यवाणी करने में समर्थ हो पाया है। यह विभाग केरल और बंगाल की खाड़ी के मौसम का अनुमान लगाने का दावा तो करता है, किंतु भारत के सबसे ज्यादा संवेदनशील क्षेत्र हिमालय में बादल फटने की भी सटीक जानकारी नहीं दे पाता है। जबकि धराली क्षेत्र में एक साथ दो जगह बादल फटे और कुछ मिनटों में हुई तेज बारिश ने श्रीखंड पर्वत से निकली खूबगंगा नदी को प्रलय में बदलकर 90 प्रतिशत गांव को हिमालय के गर्भ में समा दिया।

प्राकृतिक संपदा के दोहन से खोखला विकास

समुद्धि, उन्नति और वैज्ञानिक उपलब्धियों का चरम छू लेने के बावजूद प्रकृति का प्रकोप धरा के किस हिस्से के गर्भ से फूट पड़ेगा या आसमान से टूट पड़ेगा, यह जानने में हम बौने ही हैं। भूकंप की तो भनक भी नहीं लगती। जाहिर है, इसे रोकने का एक ही उपाय है कि विकास की जल्दबाजी में पर्यावरण की अनदेखी न करें। लेकिन विडंबना है कि घरेलू विकास दर को बढ़ावा देने के मद्देनजर अधोसंरचना विकास के बहाने देशी-विदेशी पूंजी निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है। पर्यावरण संबंधी स्वीकृतियों राज्य सरकारें अब अनदेखा करने लगी हैं। इससे साबित होता है कि अंततः हमारी वर्तमान अर्थव्यस्था का मजबूत आधार अटूट प्राकृतिक संपदा और खेती ही हैं। लेकिन उत्तराखंड हो या प्राकृतिक संपदा से भरपूर अन्य प्रदेश उद्योगपतियों की लॉबी जीडीपी और विकास दर के नाम पर पर्यावरण संबंधी कठोर नीतियों को लचीला बनाकर अपने हित साधने में लगी हैं। विकास का लॉलीपॉप प्रकृति से खिलवाड़ का करण बना हुआ है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में आई इन तबाहियों का आकलन इसी परिप्रेक्ष्य में करने की जरूरत है।

बादल फटना अनायास जरूर है, लेकिन ये करीब 10 किमी व्यास की परिधि में फटने के बाद अतिवृष्टि का कारण बनते हैं। 10 सेंटीमीटर या उससे अधिक बारिश को बादल फटने की घटना के रूप में परिभाषित किया जाता है। बादल फटने की घटना के दौरान किसी एक स्थान पर एक घंटे के भीतर, उस क्षेत्र में होने वाली औसत, वार्षिक वर्षा की 10 प्रतिशत से अधिक बारिश हो जाती है। मौसम विभाग वर्षा का पूर्वानुमान कई दिन या माह पहले लगा लेते हैं। लेकिन मौसम विज्ञानी बादल फटने जैसी बारिश का अनुमान नहीं लगा पाते। इस कारण बादल फटने की घटनाओं की भविष्यवाणी भी नहीं करते हैं।

समुद्धि, उन्नति और वैज्ञानिक उपलब्धियों का चरम छूलेने के बावजूद प्रकृति का प्रकोप धरा के किस हिस्से के गर्भ से फूट पड़ेगा या आसमान से टूट पड़ेगा, यह जानने में हम बौने ही हैं। भूकंप की तो भनक भी नहीं लगती। जाहिर है, इसे रोकने का एक ही उपाय है कि विकास की जल्दबाजी में पर्यावरण की अनदेखी न करें। लेकिन विडंबना है कि घरेलू विकास दर को बढ़ावा देने के मद्देनजर अधोसंरचना विकास के बहाने देशी-विदेशी पूंजी निवेश को बढ़वा दिया जा रहा है। पर्यावरण संबंधी स्वीकृतियों राज्य सरकारें अब अनदेखा करने लगी हैं। इससे साबित होता है कि अंततः हमारी वर्तमान अर्थव्यस्था का मजबूत आधार अटूट प्राकृतिक संपदा और खेती ही हैं। लेकिन उत्तराखंड हो या प्राकृतिक संपदा से भरपूर अन्य प्रदेश उद्योगपतियों की लॉबी जीडीपी और विकास दर के नाम पर पर्यावरण संबंधी कठोर नीतियों को लचीला बनाकर अपने हित साधने में लगी हैं। विकास का लॉलीपॉप प्रकृति से खिलवाड़ का करण बना हुआ है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में आई इन तबाहियों का आकलन इसी परिप्रेक्ष्य में करने की जरूरत है।

उत्तराखंड, उग्र से विभाजित होकर 9 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया था। 13 जिलों में बटे इस छोटे राज्य की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 1 करोड़ 11

लाख है। 80 फीसदी साक्षरता वाला यह प्रांत 53,566 वर्ग किलोमीटर में फैला है। उत्तराखंड में भागीरथी, अलकनंदा, गंगा और यमुना जैसी बड़ी और पवित्र मानी जाने वाली नदियों का



उद्गम स्थल है। इन नदियों के उद्गम स्थलों और किनारों पर पुराणों में दर्ज अनेक धार्मिक व सांस्कृतिक स्थल हैं। इसलिए इसे धर्म-ग्रंथों में देवभूमि कहा गया है। यहां के वनाच्छादित पहाड़ अनूठी जैव विविधता के पर्याय हैं। तय है,उत्तराखंड प्राकृतिक संपदाओं का खजाना है। इसी बेशकीमती भंडार को सत्ताधारियों और उद्योगपतियों की नजर लग गई है, जिसकी वजह से प्रलय जैसे प्रकोप बार-बार इस देवभूमि में बर्बादी की आपदा वर्षा रहे हैं।

उत्तराखंड की तबाही की इबारत टिहरी में गंगा नदी पर बने

बड़े बांध के निर्माण के साथ ही लिख दी गई थी। नतीजतन बड़ी संख्या में लोगों का पुरश्तेनी ग्राम-कस्बों से विस्थापन तो हुआ ही, लाखों हेक्टेयर जंगल भी तबाह हो गए। बांध के निर्माण में

विस्फोटकों के इस्तेमाल ने धरती के अंदरूनी पारिस्थिकी तंत्र के ताने-बाने को खंडित कर दिया। विद्युत परियोजनाओं और सड़कों का जाल बिछाने के लिए भी धमाकों का अनवरत सिलसिला जारी रहा। अब यही काम रेल पथ के लिए सुरंग बनाने में सामने आ रहा है। विस्फोटों से फैले मलबे को भी नदियों और हिमालयी झीलों में ढहा दिया जाता है। नतीजतन नदियों का तल मलबे से भर गए हैं।

दुर्घपरिणाम स्वरूप इनकी जलग्रहण क्षमता नष्ट हुई और जल प्रवाह बाधित हुआ। अतएव जब भी तेज बारिश आती है तो तुरंत बाढ़ में बदलकर विनाशलीला में तब्दील हो जाती है। बादल फटने के तो केदारनाथ और अब धराली जैसे परिणाम निकलते है। उत्तरकाशी, जोशीमठ में तो निरंतर बाढ़ और भू-स्खलन देखने में आ रहे हैं, इस क्षेत्र के सैकड़ों मकानों में भूमि घसंकने से बड़ी-बड़ी दरारें आ गई हैं। भू-स्खलन के अलावा इन दरारों की वजह काल्दिली और अस्मिगंगा नदियों पर निर्माणाधीन जलविद्युत और रेल परियोजनाएं भी रही हैं।

आदर्श आचरण की आवश्यकता

शिक्षा व्यवस्था
 ममता कुशवाहा
 लेखक शिक्षक हैं।

शिक्षा का शाश्वत उद्देश्य केवल ज्ञान का संचार नहीं, बल्कि चरित्र का निर्माण है। एक शिक्षक वह दीपशिखा है जो न केवल अंधकार मिटाती है, बल्कि जीवन के पथ को आलोकित करती है। किंतु जब वही दीपशिखा धुंधला पड़ने लगे, स्वयं अंधकार में डूब जाए, तब शिक्षा का मंदिर कर्लाकत हो जाता है। पंजाब के लुधियाना जिले में प्राथमिक विद्यालय की एक शिक्षिका का स्कूल में नशा करने के आरोप में निलंबन इस कटु सत्य को उजागर करता है कि शिक्षा की गरिमा केवल पुस्तकीय ज्ञान से नहीं, बल्कि शिक्षक के आदर्श आचरण से स्थापित होती है। यह घटना केवल एक विद्यालय या प्रदेश का मामला नहीं है; यह समूची शिक्षा व्यवस्था, सामाजिक जिम्मेदारी और भावी पीढ़ी के नैतिक उत्थान से जुड़ा हुआ प्रश्न है।

शिक्षक को सदैव मार्गदर्शक और प्रेरणास्रोत माना गया है। बच्चे अपने जीवन के प्रारंभिक चरण में जिस व्यक्तित्व से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं, वह है उनका शिक्षक। जब शिक्षक ही गलत आदतों का शिकार हो, अनुशासनहीन और आचरणहीन बन जाए, तब छात्रों के लिए अनुकरणीय आदर्श कहाँ से आएगा?

उक्त घटना में स्थानीय पंचायत ने बार-बार चेतावनी दी, अभिभावकों ने शिकायतें कीं, किंतु शिक्षिका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ऐसे में सरकार द्वारा निलंबन की कार्यवाही आवश्यक थी, क्योंकि शिक्षा के पवित्र वातावरण में नशे की उपस्थिति बच्चों के मानस को विकृत कर सकती है।

शिक्षकों का कर्तव्य केवल पाठ्यपुस्तक पढ़ाना नहीं, बल्कि अपने जीवन से बच्चों के लिए प्रेरणा देना है। इतिहास साक्षी है कि समाज में बड़े परिवर्तन सदैव आदर्श शिक्षकों से ही शुरू हुए हैं। डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन, महात्मा गांधी या डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम जैसे महान शिक्षकों ने यह सिद्ध किया कि शिक्षक अपने कर्म, अनुशासन और नैतिकता से लाखों छात्रों के जीवन में परिवर्तन ला सकता है। लेकिन जब शिक्षक स्वयं ही नशे की गिरफ्त में हो, अनुशासनहीन हो, तो वह दूसरों के

जीवन को कैसे संवार सकता है? यह प्रश्न न केवल शिक्षा विभाग बल्कि पूरे समाज के लिए विचारणीय है।

सरकार ने प्रदेश में नशे के कलंक को मिटाने के लिए अनेक प्रयास किए हैं। नशे के विरुद्ध अभियान में बीस हजार से अधिक नशा तस्कर सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। विद्यालयों में नशा मुक्ति के लिए पाठ्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं, कक्षा नौ से बारहवीं तक के छात्रों के लिए वैज्ञानिक कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं ताकि वे नशे के दुष्प्रभाव समझ सकें। किंतु यदि विद्यालय में ही अध्यापक नशे का सेवन करें, तो यह सारे प्रयास व्यर्थ सिद्ध हो सकते हैं।

इस समस्या का एक बड़ा कारण अभिभावकों की उदासीनता भी है। अनेक बार माता-पिता यह नहीं जानते कि उनके बच्चों को विद्यालय में कैसा वातावरण मिल रहा है, शिक्षक का आचरण कैसा है। यदि अभिभावक जागरूक हों, शिक्षकों के व्यवहार पर समय-समय पर ध्यान दें, तो ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है। अभिभावक और समाज की सतर्कता ही विद्यालयों को नैतिक और अनुशासनयुक्त बनाए रखने का सबसे मजबूत आधार है।

शिक्षा का वास्तविक अर्थ केवल रोजगार प्राप्त करना नहीं, बल्कि जीवन में नैतिकता और मूल्यों का संवर्धन करना है। जब शिक्षक स्वयं अनुशासनहीन होंगे, तो छात्रों में यह संदेश जाएगा कि अनुचित आचरण भी सामान्य है। इससे न केवल उनका भविष्य प्रभावित होगा, बल्कि समाज में भी भ्रष्टाचार, अपराध और नशाखोरी जैसी प्रवृत्तियाँ बढ़ेंगी। अतः यह अनिवार्य है कि शिक्षक स्वयं को आदर्श बनाएं। उन्हें अपने आचरण में शुचिता लानी होगी, नशे जैसी कुरीतियों से दूर रहना होगा, ताकि वे बच्चों के लिए सच्चे प्रेरणास्रोत बन सकें।

इसके लिए शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में केवल विषय ज्ञान ही नहीं, बल्कि नैतिक शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और आत्मअनुशासन पर भी विशेष बल देना आवश्यक है।

जिन शिक्षकों में नशे या अनुशासनहीनता की समस्या हो, उनके लिए पुनर्वास और परामर्श की व्यवस्था होनी चाहिए। सख्त दंडात्मक कार्रवाई के साथ-साथ सुधारात्मक प्रयास भी जरूरी हैं, क्योंकि हर शिक्षक को सुधरने का अवसर मिलना चाहिए। समाज में शिक्षक की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण है कि उनकी एक छोटी सी भूल भी बड़े परिणाम ला

सकती है। जब छात्र अपने शिक्षक को नशा करते देखेंगे, तो उनके मन में शिक्षा के प्रति सम्मान कम होगा। वहीं, यदि वे शिक्षक को ईमानदार, अनुशासित और नशामुक्त देखेंगे, तो वही बच्चे भविष्य में सच्चे नागरिक बनेंगे। यही कारण है कि नीति-निर्माताओं और समाज को मिलकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शिक्षकों का चयन और प्रशिक्षण उच्चतम नैतिक मानकों के आधार पर हो।

शिक्षा का दीपक तभी प्रज्वलित रहेगा जब उसका वाहक शिक्षक, स्वयं उजियारा होगा। नशे और अनुशासनहीनता से दूर, आत्मसंयमित, सच्चरित्र और प्रेरणादायी शिक्षक ही बच्चों के मन में ज्ञान और सुधुर्णों के बीज बो सकते हैं।

पंजाब की घटना हम सबके लिए चेतावनी है कि यदि हम शिक्षकों के आचरण पर ध्यान नहीं देंगे, तो शिक्षा का उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। इसलिए समय की माँग है कि हर शिक्षक स्वयं में सुधार लाए, अपने व्यक्तित्व को ऐसा बनाए कि छात्र उन्हें देखकर सीखने की प्रेरणा लें। तभी शिक्षा का मंदिर पावन रहेगा और आने वाली पीढ़ी उज्ज्वल भविष्य की ओर अग्रसर होगी।

प्राकृतिक आपदा
 नृपेन्द्र अभिषेक नृप
 लेखक रत्नभाकार हैं।

उत्तराखंड की वादियों में बहती गंगा की निर्मल धारा, हिमालय की ऊँची चोटियाँ और हरियाली से लिपटी घाटियाँ— इन सबका सौंदर्य भारत की प्राकृतिक धरोहर का अनुपम प्रतीक है। किंतु विगत कुछ दशकों में यह शांति का आश्रय स्थल मानवीय हस्तक्षेप और विकास की अंधी दौड़ के कारण प्रकृति के प्रकोप का अखाड़ा बनता जा रहा है। हाल ही में उत्तरकाशी में आई भीषण आपदा, जिसमें बादल फटने, भूस्खलन और बाढ़ की घटनाओं ने जन-जीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया, इस त्रासदी का नवीनतम उदाहरण है। यह केवल एक प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि मनुष्य के प्रकृति से खिलवाड़ का प्रत्यक्ष परिणाम है।

उत्तरकाशी की यह तबाही उस असंतुलित विकास की ओर इशारा करती है, जिसने पहाड़ों की नाजुक पारिस्थितिकी को भीतर तक झकझोर दिया है। पहाड़ों पर अनियंत्रित निर्माण, नदियों के किनारे कंक्रीट की इमारतें, तीर्थयात्राओं और पर्यटन के नाम पर बढ़ती मानवीय भीड़, और वनस्पति के अंधाधुंध दोहन ने पहाड़ों को असुरक्षित और संवेदनशील बना दिया है। जब पहाड़ों पर लगातार भूस्खलन का दायरा बढ़ता जा रहा है, तब भी सरकारें और प्रशासन कंक्रीट के जंगल खड़े करने से बाज नहीं आते। यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि संवेदनशील पारिस्थितिकीय क्षेत्रों में ऐसे निर्माण की अनुमति क्यों दी जाती है, जो भविष्य में तबाही का कारण बन सकता है।

प्रकृति की इस चेतावनी को केवल अचानक आई बारिश या बादल फटने जैसी घटनाओं से जोड़ना समस्या की जड़ को नकारने जैसा होगा। उत्तराखंड की पहाड़ों का स्वभाव ही तीव्र और उग्र है, किंतु जब उनके बहाव क्षेत्र में अतिक्रमण कर निर्माण किए जाते हैं, तब वे अपनी धारा को पुनः प्राप्त करने के लिए विनाशकारी रूप ले लेती हैं। नदियों के तटबंधों को काटकर होटल, घर और व्यावसायिक प्रतिष्ठान खड़े कर दिए गए हैं। नालों और जलधाराओं पर सड़कें बिछा दी गईं, जिससे वर्षा का जल प्राकृतिक मार्गों से बहने के बजाय आवासीय क्षेत्रों में घुस जाता है। इस प्रकार की गतिविधियाँ



आपदा को निमंत्रण देती हैं और जब त्रासदी घटित होती है, तब दोषारोपण का खेल शुरू हो जाता है।



उत्तरकाशी की हालिया आपदा ने एक बार फिर 2013 की केदारनाथ त्रासदी की याद ताज़ा कर दी, जब बादल

फटने और अचानक आई बाढ़ ने हजारों जिंदगियाँ लील दी थीं। उसके बाद से लेकर अब तक अनेक रिपोर्टों और चेतावनियों में यह कहा गया कि हिमालयी क्षेत्र में संवेदनशील विकास नीति अपनाई जाए। पर्यावरणविद्, वैज्ञानिक और स्थानीय समाजशास्त्री लगातार इस बात पर जोर देते रहे कि यहाँ की पारिस्थितिकी को ध्यान में रखकर निर्माण गतिविधियाँ होनी चाहिए, ताकि आपदाओं के जोखिम को कम किया जा सके। परंतु विकास के नाम पर प्यावसायिक लालच और राजनीतिक लाभ की होड़ में इन चेतावनियों को अनसुना कर दिया गया।

दरअसल, आपदाओं का मूल कारण यह है कि हमने प्रकृति को केवल संसाधन मान लिया है, जिसे बिना रोक-टोक इस्तेमाल किया जा सकता है। नदियाँ, पहाड़, जंगल और घाटियाँ, ये सब हमें जीवन देते हैं, पर हमने इन्हें कंक्रीट, डामर और लोहा-इस्पात में बदलने का अभियान छेड़ दिया है। जब नदियों के मार्ग में बाधाएँ डाली जाती हैं, जब पहाड़ों को काटकर सड़कों का जाल बिछाया जाता है, जब वृक्षों को अंधाधुंध काटकर पर्यटन स्थलों को विस्तार दिया जाता है, तब प्राकृतिक संतुलन बिगड़ना अवश्यंभावी है। इस असंतुलन का परिणाम ही है कि एक सामान्य बारिश भी तबाही का रूप ले लेती है।

उत्तरकाशी में तबाही के बाद यह प्रश्न और गहरा हो जाता है कि क्या हम विकास की सही परिभाषा समझ पाए हैं? क्या पर्यटन और तीर्थयात्राओं को बढ़ावा देने के नाम पर पहाड़ों की आत्मा को नष्ट करना विवेकपूर्ण है? विकास तभी

सार्थक होगा जब वह प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित कर आगे बढ़े। उदाहरणस्वरूप, पारंपरिक पहाड़ी वास्तुकला में ऐसे घर बनाए जाते थे जो नदियों और वर्षा के जल प्रवाह में बाधा न बनें। स्थानीय जल संवचन की प्रणालियाँ और छोटे-छोटे तालाब बाढ़ की स्थिति को संभालने में सहायक होते थे। आज इन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों की उपेक्षा कर हमने बड़े-बड़े बांध और जलाशय तो बनाए, परंतु स्थानीय पारिस्थितिक ज्ञान को तिलांजलि दे दी।

आपदा प्रबंधन के स्तर पर भी यह त्रासदी कई प्रश्न खड़े करती है। वर्षा ऋतु में जब पहले से ही भूस्खलन और बाढ़ की आशंका रहती है, तब भी सरकारें और प्रशासनिक संस्थाएँ समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाते। चेतावनी तंत्र का अभाव, आपात राहत सुविधाओं की कमी और समुचित बचाव योजनाओं का अभाव इस तबाही को और बढ़ा देता है। इसके विपरीत, यदि समय रहते नदियों के मार्ग साफ किए जाएँ, पहाड़ी जल निकासी प्रणाली को सुधार दिया जाए, और संवेदनशील क्षेत्रों में निर्माण पर कठोर नियंत्रण हो, तो आपदाओं का असर काफी हद तक कम किया जा सकता है। इस त्रासदी से एक बड़ा सबक यह भी है कि हमें विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाना होगा। उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों के लिए यह संतुलन और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ की भौगोलिक स्थिति पहले से ही नाजुक है। एक ओर पर्यटन और तीर्थयात्राओं से स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है, वहीं दूसरी ओर बढ़ते निर्माण और भीड़ के दबाव से पारिस्थितिकी संकट में पड़ जाती है। इसका समाधान यही है कि हम सतत विकास मॉडल अपनाएँ, जहाँ पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक प्रगति एक-दूसरे के पूरक हों, विरोधी नहीं।

उत्तरकाशी की तबाही केवल एक घटना नहीं, बल्कि भविष्य की चेतावनी है। यदि हमने अब भी प्रकृति के संकेतों को नहीं समझा, तो आने वाले वर्षों में ऐसी आपदाएँ और भी विनाशकारी रूप लेंगी। हमें विकास की दिशा बदलनी होगी, ऐसी दिशा जिसमें नदियों को उनका प्राकृतिक प्रवाह मिले, पहाड़ों की स्थिरता बनी रहे, और मनुष्य का अस्तित्व प्रकृति के साथ सामंजस्य में पनपे। यही राह राह है जो न केवल उत्तरकाशी, बल्कि पूरे हिमालयी क्षेत्र को सुरक्षित रख सकती है।



‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान के तहत

एमसीयू NSS इकाई ने किया वृक्षारोपण

भोपाल। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल की राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) इकाई द्वारा आज विश्वविद्यालय परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विश्वविद्यालय के कुलगुरु विजय मनोहर तिवारी के नेतृत्व में हुआ। राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी डॉ. गजेंद्र सिंह अवास्या एवं सुश्री मनीषा वर्मा उपस्थित रही। सभी ने मिलकर पर्यावरण संरक्षण की महता पर प्रकाश डाला और 'एक पेड़ माँ के नाम' जैसे अभियानों को सामाजिक चेतना से जोड़ने की सराहना की। इस अवसर पर NSS के वरिष्ठ स्वयंसेवकों – श्री ओम दांगी, प्रतीत चांडक, केशव कुशवाहा, सौरभ सिंह, हरिओम गुप्ता, नमन आदि ने सक्रिय सहभागिता दिखाई। इसके साथ ही बड़ी संख्या में नवागत विद्यार्थियों ने भी वृक्षारोपण में उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान सभी प्रतिभागियों ने अपने-अपने हाथों से आम के पौधे लगाए और उन्हें संरक्षित करने का संकल्प लिया। यह आयोजन विश्वविद्यालय के सामाजिक उत्तरदायित्व और पर्यावरण के प्रति जागरूकता के संकल्प को और सशक्त करता है।

राज्यपाल से मध्यप्रदेश ह्रीलचेयर

क्रिकेट और दिव्यांग महिला क्रिकेट टीम

के सदस्यों ने की मुलाकात

राज्यपाल ने उत्साहवर्धन कर दी शुभकामनाएं

भोपाल (नप्र)। राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल से मंगलवार को मध्यप्रदेश व्हीलचैयर क्रिकेट और दिव्यांग महिला क्रिकेट टीम के सदस्यों ने राजनवन में मुलाकात की। राज्यपाल श्री पटेल को दिव्यांग महिला क्रिकेट टीम की कप्तान राधा बहुगुज्जर ने 'उमंग' 

कप' में जीती गई ट्रॉफी भेंट की। राज्यपाल श्री पटेल ने टीम के सदस्यों को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी। राज्यपाल श्री पटेल ने मध्यप्रदेश व्हीचेयर क्रिकेट और दिव्यांग महिला टीम के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और उनकी उपलब्धियां जानी। उन्होंने दोनों टीम के सदस्यों का उत्साहवर्धन करते हुए उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं। खिलाड़ियों के साथ सामूहिक चित्र भी खिंचवाया। इस अवसर पर राज्यपाल के प्रमुख सचिव डॉ. नवनीत मोहन कोठारी भी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानी सर

सुरेंद्रनाथ बनर्जी को दी श्रद्धांजलि

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सहानुस्वतंत्रता सेनानी सर सुरेंद्रनाथ बनर्जी की 100वीं पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि स्वतंत्रता के लिए वैचारिक ज्योति प्रज्वलित करने वाले सर बनर्जी ने इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना सहित अनेक अभूतपूर्व कार्य किए। उनके प्रयासों से ब्रिटिश शासन की दमनकारी व्यवस्था बेनकाब हुई। सर बनर्जी का निधन 6 अगस्त 1925 को हुआ था।

ट्रक की टक्कर से 2-युवकों

के सिर धड़ से अलग

कटनी (नप्र)। कटनी में बुधवार शाम करीब 5 बजे पीराबाबा के पास सड़क हादसे में दो युवकों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। ट्रक की टक्कर से दोनों के सिर धड़ से अलग हो गए। लोगों के मुताबिक, टक्कर इतनी तेज थी कि एक का शव 50 मीटर दूर जाकर गिरा।मृतक युवकों की पहचान विजयरावगढ़ थाना क्षेत्र के उबरा गांव निवासी आदित्य चतुर्वेदी और गुणगु मिश्रा के रूप में हुई। दोनों युवक एफिटवा से पीराबाबा की ओर जा रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रहेट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ट्रक की रफ्तार बहुत तेज थी। टक्कर से एफिटवा के परखच्चे उड़ गए। माधवनगर पुलिस को घटना की सूचना मिलते ही टीआई अभिषेक चौबे अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शकों को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल रवाना किया। पुलिस ने दुर्घटना को अंजाम देने वाले ट्रक और चालक की तलाश शुरू कर दी है।

अनुसूचित जाति विभाग का सामाजिक

न्याय कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न

दलित और वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा का संकल्प

भोपाल। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित जाति विभाग द्वारा आज आयोजित सामाजिक न्याय कार्यक्रम बड़े उत्साह और सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम अनुसूचित जाति, दलित और वंचित समुदायों के समस्याओं, राजनीतिक और आर्थिक सशक्तिकरण पर केंद्रित रहा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेसजन, जनप्रतिनिधि, समाजसेवी और विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था- अनुसूचित जाति और दलित समुदायों के सामने मौजूद सामाजिक चुनौतियों पर विचार-विमर्श। समानता, न्याय और अवसर सुनिश्चित करने के लिए ठोस रणनीति तैयार करना। वंचित समाज के अधिकारों की रक्षा और उनके राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में कदम उठाना।

कार्यक्रम के प्रमुख वक्ता और अतिथिगण- इस अवसर पर अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजेंद्र पाल गौतम ,श्री जीतू पटवारी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष,श्री उमंग सिंगार, नेता प्रतिपक्ष,श्री महेश परमार, विधायक,श्री जयवर्धन सिंह, विधायक,श्री सुरेश राजे, वरिष्ठ नेता,श्री लखन गंगोरिया, विधायक,डॉ. विजय लक्ष्मी साधो, पूर्व मंत्री,श्री सुखदेव पांस, वरिष्ठ नेता,श्री सज्जन सिंह वर्मा, पूर्व मंत्री,श्री ह्दक प्रजापति, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष,श्री प्रदीप अहिरवार,श्री हेमंत नरवरिया, डॉ. विक्रम चौधरी, अजय अहिरवार सहित प्रदेश के अनेक वरिष्ठ कांग्रेसजन और अनुसूचित जाति विभाग के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

जनपद

एम्स की डॉ. रुपिंदर छाईं टाइम्स स्कायर न्यूयॉर्क पर

फॉर्चुना ग्लोबल एक्सीलेंस अवॉर्ड्स से मिली अंतरराष्ट्रीय पहचान, दुनिया के प्रभावशाली 100 लीडर्स में आया नाम

भोपाल (नप्र)। एम्स भोपाल की ट्रांसलेशनल मेडिसिन विभाग की प्रमुख और रिसर्च की एसोसिएट डीन, डॉ. रुपिंदर कौर कंवर को बायोमेडिकल रिसर्च लीडर ऑफ द ईयर (इंडिया) का खिताब मिला है। यह सम्मान उन्हें फॉर्चुना ग्लोबल एक्सीलेंस अवॉर्ड्स (इंडिया एडिशन) के तहत दिया गया है। यही नहीं, डॉ. कंवर का नाम दुनिया के सबसे प्रभावशाली 100 लीडर्स की सूची 'फॉर्चुना ग्लोबल 100: द पावर लिस्ट 2025' में भी आया है। जिसकी घोषणा न्यूयॉर्क के टाइम्स स्कायर में की गई। यह सूची हेल्थकेयर और बायोमेडिकल इनोवेशन में दुनिया भर के टॉप 100 लीडर्स को सम्मानित करती है।



यह सम्मान डॉ. कंवर को उनकी दूरदर्शिता, वैल्यू-बेस्ड लीडरशिप और ट्रांसलेशनल मेडिसिन को आगे बढ़ाने के प्रयासों के लिए दिया गया। फॉर्चुना

मैगजीन ने उन्हें भारत में ट्रांसलेशनल मेडिसिन को नई दिशा देने वाली पहली वैज्ञानिक बताया है।

शोध और नवाचार में आगे

आगामी 4 दिन बारिश के आसार नहीं, लोग गर्मी-उमस से परेशान, अस्पताल में बड़े मरीज, किसान चिंतित

बारिश की खेंच से सूखने लगी हल्की जमीन की फसलें



जिले में अभी 2584 मीट्रिक टन खाद उपलब्ध है। जबकि 63182 मीट्रिक टन खाद का वितरण किया जा चुका है। इसके अलावा जिले को लगातार खाद मिल रही है। कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कृषक यूरिया के लिए जल्दबाजी न करें। लगातार यूरिया की रैक जिले को मिल रही है। उतना ही यूरिया ले जितना तत्काल जरूरत हो। यूरिया से अधिक उपयोगी नैनी यूरिया प्लस का उपयोग अधिक लाभप्रद है। इसे भी कुछ क्षेत्र में जरूर उपयोग करें। अधिकारियों

का कहना है कि सोसायटियों में लगातार खाद की सप्लाई जारी है। सभी किसानों को पर्याप्त खाद दिया जायेगा। खाद को लेकर किसानों को परेशान नहीं होने दिया जाएगा।

10 अगस्त से फिर सक्रिय हो

खकता है मानसून

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, अब 10 या 11 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक फिर से बारिश शुरू होने के संकेत हैं। इस दौरान अच्छी वर्षा होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं, सितंबर में भी

अच्छी बारिश की उम्मीद है। विशेषज्ञों के मुताबिक, मानसून टूट लाइन के उत्तर की ओर तराई क्षेत्र में चले जाने से बारिश पर असर पड़ा है। हालांकि बंगाल की खाड़ी में डिप्रेशन बनने की संभावना है, जिससे आने वाले दिनों में मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र में अच्छी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने अगले 3-4 दिनों तक बारिश की संभावना बहुत कम जताई है। केवल 20 प्रतिशत तक बारिश की उम्मीद है, लेकिन वर्तमान मौसम को देखकर भारी बारिश के आसार नहीं हैं।

संविदा कर्मचारियों की नियमितीकरण की मांग

को लेकर बिजली कर्मचारियों ने निकाली रैली

भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले बिजली कर्मचारी महासंघ ने प्रबंध संचालक के नाम सौंपा ज्ञापन

बैतूल। संविदा पर कार्यरत बिजली कर्मचारियों को नियमित किए जाने की मांग को लेकर बुधवार को भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध बिजली कर्मचारी महासंघ के नेतृत्व में रैली निकाली गई। इसके पश्चात प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल के नाम महाप्रबंधक संचा/संथा, मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड बैतूल वृत्त को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपते हुए पूर्व प्रदेश महामंत्री मधुकर साबले ने कहा कि संविदा कर्मचारियों की मांगें पूरी तरह से जायज हैं और लंबे समय से नियमितीकरण की मांग को लेकर संघर्ष किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि



भारतीय मजदूर संघ इन मांगों को लेकर गंभीर है और हर स्तर पर प्रयास कर रहा है ताकि कर्मचारियों को उनका हक मिल सके। रैली में बड़ी संख्या में संविदा कर्मचारी उपस्थित रहे। रैली के बाद बिजली कर्मचारी महासंघ के कार्यकर्ताओं द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन का वाचन महासंघ के सचिव विजय यादव ने किया। कार्यक्रम का समापन भी अध्यक्ष चंद्रभान पंडगे द्वारा किया गया। ज्ञापन सौंपने वालों में भारतीय मजदूर संघ के पूर्व महामंत्री मधुकर साबले, विभाग प्रमुख विनय डोंगरे, अध्यक्ष संपत दरवाई, जिला मंत्री पंजाबराव गायकवाड, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य राजेश मंसूरिया, पर्वतार व ठाकरे, बिजली कर्मचारी महासंघ के वृत्त अध्यक्ष चंद्रभान पंडगे, सचिव विजय यादव, संतोष शिंदे, संतोष गुप्ता, निरंजन सिंह, रामकिशोर सोनी, निशांत मेश्राम, कुलदीप ठाकरे सहित अन्य संविदा कर्मचारी शामिल थे।

भारतीय मजदूर संघ इन मांगों को लेकर गंभीर है और हर स्तर पर प्रयास कर रहा है ताकि कर्मचारियों को उनका हक मिल सके। रैली में बड़ी संख्या में संविदा कर्मचारी उपस्थित रहे। रैली के बाद बिजली कर्मचारी महासंघ के कार्यकर्ताओं द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन का वाचन महासंघ के सचिव विजय यादव ने किया। कार्यक्रम का समापन भी अध्यक्ष चंद्रभान पंडगे द्वारा किया गया। ज्ञापन सौंपने वालों में भारतीय मजदूर संघ के पूर्व महामंत्री मधुकर साबले, विभाग प्रमुख विनय डोंगरे, अध्यक्ष संपत दरवाई, जिला मंत्री पंजाबराव गायकवाड, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य राजेश मंसूरिया, पर्वतार व ठाकरे, बिजली कर्मचारी महासंघ के वृत्त अध्यक्ष चंद्रभान पंडगे, सचिव विजय यादव, संतोष शिंदे, संतोष गुप्ता, निरंजन सिंह, रामकिशोर सोनी, निशांत मेश्राम, कुलदीप ठाकरे सहित अन्य संविदा कर्मचारी शामिल थे।

गोविंदगढ़ में बाघ प्रजनन केन्द्र एवं कर्नाटक के पीलीकुला बायोलॉजिकल पार्क के बीच वन्यप्राणियों के आदान-प्रदान की कार्यवाही की समीक्षा की

प्रदान प्रस्ताव को शीघ्र अंतिम रूप देने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि गोविंदगढ़ के बाघ प्रजनन केन्द्र को

अब तक 300 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित

133 हार्ड-इपैक्ट जर्नल आर्टिकल्स,

26 पुस्तक अध्याय

22 अंतरराष्ट्रीय पेटेंट, जो अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर और न्यूजीलैंड में दर्ज

नैनोमेडिसिन, रिजनरेटिव मेडिसिन, ट्रांसलेशनल रिसर्च और ड्रग डिस्कवरी में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता

नई पहल और उपलब्धियां

2024 में भारत का पहला एमएससी इन ट्रांसलेशनल मेडिसिन प्रोग्राम शुरू किया। ऐसे रिसर्च और डायग्नॉस्टिक प्लेटफॉर्म विकसित किए, जो स्थानीय

स्वास्थ्य आवश्यकताओं को वैश्विक मानकों से जोड़ते हैं।

एम्स भोपाल को सम्पत्ति किया सम्मान

डॉ. कंवर ने कहा, यह सम्मान केवल मेरा नहीं, बल्कि एम्स भोपाल और भारतीय बायोमेडिकल रिसर्च समुदाय का है। हमारा लक्ष्य है कि हम भारत को हेल्थकेयर इनोवेशन में वैश्विक लीडर बनाएं। फॉर्चुना ग्लोबल एक्सीलेंस अवॉर्ड्स को सबसे विश्वसनीय अंतरराष्ट्रीय सम्मान माना जाता है। इसका चयन पूरी तरह पारदर्शी प्रक्रिया और विशेषज्ञ जूरी द्वारा किया जाता है। टाइम्स स्कायर पर नाम आने से एम्स भोपाल की ग्लोबल पहचान और मजबूत हो गई है।

फांसी लगाकर अघेड़ ने

की आत्महत्या, पुलिस

कर रही जांच

बैतूल। बैतूल में सोनाघाटी पुलिस चौकी के क्षेत्र में रहने वाले 58 साल के व्यक्ति की सद्विध परिस्थितियों में मौत हो गई है। मृतक प्रभाकर ठाकरे भारत भारती परिसर में रहते थे और मजदूरी करके अपने परिवार का पालन-पोषण करते थे। बुधवार देर रात करीब 1 बजे मृतक प्रभाकर को आखिरी बार देखा गया था। वे उस समय कोठे की ओर गए थे। सुबह जब परिजनों ने उन्हें नहीं देखा तो पहले यही समझा कि वे खेत की ओर चले गए होंगे। लेकिन सुबह 5 बजे उनका शव घर के कोठे में फांसी पर लटका मिला। इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। परिजनों के अनुसार, प्रभाकर नियमित रूप से शराब का सेवन करते थे। घटना की रात भी उन्होंने शराब पी थी। बेटे पवन ने बताया कि रात में उन्होंने करीब एक बजे तक टीवी पर न्यूज देखी। फिर वे बाथरूम गए। लौटकर आने के बाद फिर सोने चले गए। रात में घर का पिछला दरवाजा खुला होने पर परिवार को लगा कि वे खेत गए होंगे। सुबह जागने पर पत्नी ने उन्हें घर के पीछे कोठे में फांसी पर लटका पाया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा बनाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। शव के आसपास कोई संवर्ध या चोट के निशान नहीं मिले हैं। पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है।

कन्या महाविद्यालय में स्तनपान

जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन

बैतूल। शासकीय कन्या महाविद्यालय बैतूल में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई



एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त तत्वावधान में एक दिवसीय स्तनपान जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं को स्तनपान के महत्व एवं इससे जुड़े स्वास्थ्य लाभों के प्रति जागरूक करना था। संगोष्ठी की मुख्य वक्ता अर्चना तिवारी (महिला एवं बाल विकास) रही, जिन्होंने स्तनपान से शिशु को होने वाले स्वास्थ्य लाभों पर विस्तार से प्रकाश डाला। विशेष वक्ता श्रीमती श्वेता वालंबे (महिला एवं बाल विकास) ने माताओं के स्वास्थ्य पर स्तनपान के सकारात्मक प्रभावों पर व्याख्यान दिया। वहीं, चिकित्सक डॉ. शोतल मोरे ने स्तनपान के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों की जानकारी दी। डॉ. साधना ड्हेरिया ने भी स्तनपान के महत्व पर छात्राओं को संबोधित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. विद्या चौधरी ने की। उन्होंने छात्राओं से आग्रह किया कि वे स्तनपान के प्रति समाज में जागरूकता फैलाने में सक्रिय भूमिका निभाएं। कार्यक्रम का संचालन रासेयो कार्यक्रम अधिकारी डॉ. मेधा मालवी ने किया तथा सरिता झारे ने अतिथियों एवं प्रतिभागियों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर महाविद्यालय के शिक्षकगण, कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में छात्राएं उपस्थित रहीं। संगोष्ठी ने छात्राओं में स्तनपान जैसे महत्वपूर्ण विषय को लेकर जागरूकता बढ़ाने में एक प्रभावी पहल की।

स्व. सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी की 100वीं जयंती एवं पूर्व पीसीसी

अध्यक्ष श्रीमती उर्मिला सिंह जी को श्रद्धांजलि

भोपाल। आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय (पीसीसी), भोपाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी की 100वीं जयंती एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती उर्मिला सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर संगठन महामंत्री डॉ संजय कामले जी ,वरिष्ठ नेता महेंद्र सिंह चौहान जी,आनंद तारण जी, अनिल मार्टिन जी, अनिल जाधव जी, सीता शरण सूर्यवंशी जी, मुजफ्फर अली जी, अनोश गुड्डु जी, चंद्र साहब जी, बिंदे सिंह जी, रघु पाटिल जी, शहजाद खान जी, अभिषेक शर्मा जी, मोईन सिद्दीकी जी, सहित प्रदेश कांग्रेस के अनेक वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम में नेताओं ने स्व. सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी और श्रीमती उर्मिला सिंह जी के योगदान को याद करते हुए पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उपस्थित नेताओं ने उनके जीवन और कार्यों से प्रेरणा लेते हुए संगठन की मजबूती और समाज सेवा के लिए कार्य करने का संकल्प लिया।

तकनीकी शिक्षा विभाग की परामर्शदात्री समिति की बैठक

भोपाल (नप्र)। उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री इन्दर सिंह परमार की अध्यक्षता में बुधवार को विधानसभा स्थित समिति कक्ष में तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग की परामर्शदात्री समिति की बैठक हुई। बैठक में विधायक सर्वश्री हरिबबू राय, इंजीनियर श्री नरेंद्र प्रजापति, श्री अशोक रोहणी, डॉ तेज बहादुर चौहान, डॉ राजेंद्र पाण्डेय (राजु भैया), प्रमुख सचिव तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार श्री मनीष सिंह, संचालक कौशल विकास श्री गिरीश शर्मा और आयुक्त तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार श्री अवधेश शर्मा सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।



बैठक में शासकीय योजनाओं, गतिविधियों एवं कार्यक्रमों के व्यापक प्रचार-प्रसार एवं कार्यक्रमों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित करने के सुझाव विधायकों ने दिये। विधायकों ने स्थानीय उद्योग जगत की मांग एवं स्थानीय रोजगार की संभावनाओं के अनुरूप संस्थान एवं पाठ्यक्रमों के संचालन के सम्बन्ध में भी महत्वपूर्ण परामर्श दिए। इंजीनियरिंग, पॉलीटेक्निक एवं आईटीआई संस्थानों में अधिकाधिक सीट भरने के लिए आवश्यक सुझाव भी विधायकों ने दिए।

तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री परमार ने विधायकगणों से प्राप्त विभिन्न सुझावों के अनुरूप आवश्यक कार्ययोजना बनाकर क्रियान्वयन के लिए सम्बंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में पिछली बैठक का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। इंजीनियरिंग, पॉलीटेक्निक एवं आईटीआई महाविद्यालयों में प्रवेश का अद्यतन परिदृश्य, तकनीकी शिक्षा, कौशल एवं रोजगार संचालनालय अंतर्गत संचालित विभिन्न शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन की अद्यतन स्थिति, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय एवं ग्लोबल रिकल्स पार्क की गतिविधियों, संस्थान एवं पाठ्यक्रम, विभिन्न छात्रवृत्ति, पदपूर्ति की प्रक्रिया एवं भर्तियों की अद्यतन स्थिति, विभागीय कार्यों एवं नवाचारों पर क्रियान्वयन, सकल्प पत्र के अनुरूप विभागीय क्रियान्वयन की प्रगति, विभिन्न बोर्ड अंतर्गत संचालित योजनाओं, विभिन्न इंटरनशिप योजनाओं, स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन, रोजगार मेला एवं विद्यार्थियों के अध्ययन-अध्यापन और रोजगार से जुड़े विविध विषयों पर सार्थक चर्चा हुई। स्थानीय एवं उद्योग जगत की मांग एवं आवश्यकतानुरूप संस्थान एवं पाठ्यक्रमों पर भी विस्तृत चर्चा की गई।

मुख्यमंत्री ने सुषमा स्वराज की पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पूर्व केंद्रीय विदेश मंत्री स्व. श्रीमती सुषमा स्वराज 'दीदी' की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि स्व. सुषमा दीदी का बहुआयामी व्यक्तित्व, ओजस्वी वाणी, गहन चिंतन और राष्ट्र के प्रति उनका अटूट समर्पण हम सभी के लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत रहेगा। उन्होंने कहा कि जनसेवा और कर्तव्यनिष्ठा की प्रतिमूर्ति सुषमा जी ने भारतीय राजनीति को नई दिशा दी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सुषमा जी ने केन्द्रीय विदेश मंत्री के रूप में जिस संवेदशीलता और तत्परता से देशवासियों की सहायता की, वह आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। उनके कुशल नेतृत्व और मातृवत स्नेह से भरी राजनीति आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करती रहेगी।



मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को इंदौर में प्रदेश के सबसे बड़े वॉटर पार्क इमेजिका एका का वर्चुअल लोकार्पण किया। इस मौके पर जल ससाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट भी उपस्थित थे।

रक्षाबंधन पर साफ रहेगा मौसम...तेज बारिश नहीं

एमपीमें अगले 4 दिन स्ट्रॉंगसिस्टम नहीं; तीखी धूप खिली रहेगी

भोपाल (नप्र)। अबकी बार जून-जुलाई में मानसून जमकर बरसा, लेकिन अगस्त में तेज बारिश का दौर थम गया है। पिछले एक सप्ताह से रिमझिम बारिश हो रही है। अगले 4 दिन तक स्ट्रॉंग सिस्टम की एक्टिविटी नहीं है। ऐसे में रक्षाबंधन पर भी मौसम साफ रहेगा। मौसम विभाग की माने तो भोपाल, इंदौर, उज्जैन समेत सभी जिलों में तीखी धूप खिली रहेगी।



मौसम विभाग ने 9 अगस्त तक प्रदेश में कहीं भी तेज बारिश होने का अनुमान नहीं जताया है। इसकी वजह स्ट्रॉंग सिस्टम की एक्टिविटी नहीं है। उत्तरी हिस्से में जरूर हल्की बारिश हो सकती है। बारिश थमने से गर्मी का असर बढ़ेगा। ज्यादातर शहरों में पारा 35 डिग्री के पार रहेगा।

अब तक 28.7 इंच बारिश, 44 प्रतिशत ज्यादा- प्रदेश में इस मानसूनी सीजन में 28.7 इंच बारिश हो चुकी है। अब तक 44 प्रतिशत पानी ज्यादा गिर चुका है। वहीं, कोटे की 77 प्रतिशत है। पूर्वी हिस्से में बावल जमकर बरसे हैं। मौसम विभाग के अनुसार, अगस्त के दूसरे सप्ताह में तेज बारिश का दौर शुरू होगा, जो आखिरी तक चलता रहेगा। ऐसे में बारिश का कोटा अगस्त में ही पूरा हो जाएगा। हालांकि, अब तक ग्यालियर समेत 9 जिलों में कोटा पूरा हो चुका है, लेकिन इंदौर और उज्जैन संभाग के जिलों की तस्वीर बेहतर नहीं है।

आपदा प्रबंधन को छोड़ बाकी कामों से अफसरों की दूरी

न्यायिक-गैर न्यायिक विभाजन से नाराज तहसीलदार, भोपाल में भी विरोध

भोपाल (नप्र)। राजस्व अधिकारियों के न्यायिक और गैर न्यायिक विभाजन को लेकर बुधवार से विरोध हो रहा है। तहसीलदार और नायब तहसीलदार आपदा प्रबंधन को छोड़ अन्य कोई काम नहीं कर रहे हैं। भोपाल में भी नई व्यवस्था का विरोध है। इस बारे में राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने कहा कि यह कैबिनेट का निर्णय है। सभी तहसीलदारों के लिए व्यवस्था नहीं है।

भोपाल में बैरगढ़, कोलार, एमपी नगर, शहर वृत्त, बैरसिया और टीटी नगर तहसीलें हैं। इनके तहसीलदार और नायब तहसीलदारों को न्यायिक और गैर न्यायिक कार्य में विभाजित किया गया है। यानी, जो अधिकारी न्यायिक कार्य कर रहे हैं, वे फ़िल्ड में नहीं है।

वहीं, फ़िल्ड वाले अधिकारी न्यायिक कार्य नहीं कर रहे। इस व्यवस्था का वे भी विरोध कर रहे हैं। बुधवार को कोर्ट समेत अन्य काम उन्होंने नहीं किए। इस वजह से आमजनों के कामकाज पर भी असर पड़ रहा है।



●मंत्री बोले-पहले दिक्कतें आ रही थीं- विरोध के चलते राजस्व मंत्री वर्मा ने बताया कि कैबिनेट का निर्णय है। प्रोटोकॉल और न्यायालयीन प्रक्रिया में पहले बड़ी दिक्कतें आ रही थीं। सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदारों के लिए व्यवस्था नहीं की है। कुछ के लिए ही है। ●पहले भी मंत्री-अफसरों को सुना चुके बात- इस संबंध में मध्यप्रदेश राजस्व अधिकारी (कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा) संघ राजस्व मंत्री वर्मा और सीनियर

अधिकारियों के सामने अपनी बात रख चुका है। इस दौरान बताया गया था कि अगले 3 महीने के लिए 12 जिलों में ही पालेट प्रोजेक्ट के तहत यह व्यवस्था लागू की जाएगी, लेकिन बाद में 9 और जिलों में यह व्यवस्था लागू कर दी गई। इसके चलते संघ के सभी जिला अध्यक्ष, प्रभारी और प्रतिनिधियों की बैठक हुई। इसमें 6 अगस्त से विरोध करने का फिर से निर्णय लिया गया। संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष नवीनकुंद कुंभकार ने बताया कि

भोपाल, इंदौर, उज्जैन समेत प्रदेश के कई जिलों में राजस्व अधिकारी विरोध कर रहे हैं। ●यह कर रहे राजस्व अधिकारी- बुधवार से राजस्व अधिकारी जिला मुख्यालयों में उपस्थित रहकर आपदा प्रबंधन के कार्यों को छोड़कर समस्त कार्यों से बिरत है। सभी अधिकारी अपने शासकीय वाहन जिलों में जमा करा देंगे और अपने डिजिटल सिग्नेचर के डोंगल सीलबंद कर एकत्र कर जिला अध्यक्ष को सौंपेंगे।

एडवांटेज-ओवरसीज ने 100 गुना टर्नओवर दिखाकर लिया लोन

एसबीआई से 1266 करोड़ का फ्रॉड किया, सर्चिंग में ईडी को 300 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी मिली

भोपाल (नप्र)। ईडी भोपाल की टीम ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 1266 करोड़ का लोन लेकर खुद को एनपीए (नॉन परफॉर्मिंग एसेट) बताने वाली मेसर्स एडवांटेज ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड के यहां सर्चिंग कर 300 करोड़ रुपए से अधिक की प्रॉपर्टी और नकदी जब्त की है।

ईडी ने बैंक के साथ फ्रॉड करने वाले कंपनी के डायरेक्टर्स, कर्मचारियों और बेनामीदारों के नाम पर संपत्तियां अर्जित की और बैंक से लिए गए लोन का आपराधिक इस्तेमाल किया। ईडी की जांच में मिले दस्तावेजों से कंपनी द्वारा देश-विदेश में बैंक से लिए गए लोन का उपयोग करने के सबूत मिले हैं।

आपराधिक आय को वैध बनाने से जुड़े दस्तावेज मिले- प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 4 अगस्त को पीएमएलए 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स एडवांटेज ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड (एओपीएल) के ठिकानों पर सर्चिंग की है। सर्चिंग के दौरान इन ठिकानों से ऐसे दस्तावेज भी मिले, जो



आपराधिक आय को वैध बनाने से संबंधित हैं। साथ ही सद्विध लेन-देन के जरिए अत्यधिक महंगी प्रॉपर्टीज को कर्मचारियों और बेनामीदारों के नाम पर रखा गया। इसके लिए बेनामी कंपनियों का भी इस्तेमाल किया गया।

सीबीआई की एफआईआर के आधार पर शुरू की जांच- ईडी ने सीबीआई बीएसएफसी नई दिल्ली द्वारा आईपीसी 1860 की अलग-अलग धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की आई कार्रवाई के आधार पर यह सर्चिंग की है।

सीधी में दलित युवती से गैंगरेप

पीड़िता का मुंह दबाकर जंगल में घसीटकर ले गए 4 आरोपी, प्रेमी के सिर में डंडा मारा, 3 गिरफ्तार

सीधी (नप्र)। सीधी में दलित युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया है। युवती अपने प्रेमी के साथ जंगल में घूमने और फोटो खिंचाने गई थी। यहां चार बदमाशों ने युवक पर हमला कर दिया। इसके बाद युवती से गैंगरेप किया। पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक फरार है।

घटना चुरहट के जंगल की है। मंगलवार को वारदात के बाद पीड़िता रोती-बिलखती जंगल से बाहर गांव में आईं। उसने भवन निर्माण का काम कर रहे लोगों से मदद मांगी और आपबीती सुनाई। सरपंच पति दलबीर सिंह को युवती ने बताया कि वह प्रेमी के साथ जंगल से बाहर आने के लिए नीचे उतर रही थी, तभी आरोपियों ने उसका मुंह



दबा दिया और उसके प्रेमी के सिर पर डंडा मारा। वह जमीन पर गिर पड़ा।

दो आरोपी पीड़िता को जंगल की ओर खींचकर ले गए, जबकि दो युवक प्रेमी को पकड़े

रहे। पीड़िता ने बताया कि वह गिड़गिड़ाती रही। उसने आरोपियों के पैर भी पकड़े, लेकिन वे नहीं माने।

दोनों के मोबाइल छीनकर भागे आरोपी- पीड़िता ने बताया कि आरोपियों ने उन्हें धमकाया कि अगर किसी को बताया तो दोनों को जान से मार देंगे। दोनों के मोबाइल भी छीन लिए। किसी तरह खुद को संभालते हुए पीड़िता जंगल से दोपहर करीब 2.30 बाहर आईं। इसके बाद दलबीर सिंह ने पुलिस को सूचना दी। कुछ देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जंगल में गई। वहां एक टॉवल और कुछ जगहों पर संघर्ष के निशान मिले। वहीं, पुलिस पूरी रात गांव-गांव जाकर पूछताछ करती रही।

हरदा में यूरिया खत्म होने पर किसानों का हंगामा

रात से लाइन में लगे, कलेक्ट्रेट पहुंचकर किया हंगामा; एक किसान की तबीयत बिगड़ी

हरदा (नप्र)। हरदा में मंगलवार-बुधवार की दरमियानी रात से लाइन में खड़े किसानों को टोकन मिलने के बाद भी यूरिया नहीं मिल पाई। बुधवार दोपहर नाराज किसानों ने पुलिस की मौजूदगी में हंगामा कर यूरिया उपलब्ध कराने की मांग की। जब उन्हें गोदामों में स्टॉक खत्म होने की जानकारी मिली तो वो कलेक्ट्रेट पहुंच गए। उन्होंने प्रशासन से खाद उपलब्ध कराने की मांग की है। इस दौरान तेज धूप और गर्मी में लाइन में खड़े लखौरा गांव निवासी अर्जुन कोर की तबीयत खराब हो गई।

तब दै कि इस साल किसानों ने सोयाबीन की जगह मक्का की खेती का रकबा तीन गुना बढ़ाया है, लेकिन समय पर यूरिया न मिलने से फसल को नुकसान का खतरा बढ़ रहा है। मालवार को प्रशासन ने एमपी एग्री,



डीएमओ गोदाम और सोसाइटी के माध्यम से खाद वितरण की जानकारी दी, जिसके बाद सैकड़ों किसान देर शाम से ही गोदामों पर पहुंच गए। किसान बैरिकेड के बीच मच्छों से जूझते हुए रात भर जागकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं।

प्राइवेट डीलरों के नाम

सर्वजनिक नहीं किए, डीएमओ गोदाम पर लगी भीड़- विपणन संघ के प्रबंधक योगेश मालवीय ने बताया कि बुधवार को जिले में 1 हजार 100 मेट्रिक टन यूरिया कोर्पोरेटिव एवं 300 मेट्रिक टन यूरिया प्राइवेट डीलरों को दिया गया। जिला मुख्यालय पर मार्केफंड के दो,

प्राइवेट के दो एवं एमपी एग्री के एक गोदाम से यूरिया वितरण किया गया। इसके अलावा करीब 11 सोसायटियों को भी यूरिया भेजा गया। कृषि विभाग ने प्राइवेट डीलरों के नाम सार्वजनिक नहीं किए, जिसके चलते डीएमओ गोदाम पर किसानों की भीड़ लग गई।

बारी आने तक खत्म हुआ खाद- बुधवार दोपहर एक बजे खाद लेने लाइन में लगे किसानों के बीच धक्का-मुक्की होने लगी। वहां तीन थानों की पुलिस को तैनात किया गया है। पुलिस ने किसानों को धूप से बचाने के लिए खुद टोकन बांटना शुरू किया है। किसानों का कहना है कि अब उन्हें फसल बचाने के लिए यूरिया की तत्काल जरूरत है। इसलिए वे पूरी रात लाइन में रहकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं।

प्रशासन को समय में पूरी करनी थी खाद की डिमांड- हरदा विधायक डॉ आर के दौगने ने किसानों के यूरिया के लिए परेशान होने और देर रात से लाइन में लगने के मुद्दे को लेकर कहा कि वो कलेक्टर और कृषि अधिकारी से लगातार बात कर रहे हैं। लेकिन फिर भी व्यवस्था नहीं बन पा रही। उन्होंने बताया कि प्रशासन के पास जिले में कुल जितनी भी जमीन है इसका पूरा रिकॉर्ड है।

खाद लेने के साथ उपज बेचने के लिए परेशान हैं किसान- इसके बाद भी पहले से डिमांड नहीं भेजी गई है, जिसके चलते किसानों को परेशान होना पड़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों खाद लेने के साथ-साथ अपनी उपज बेचने के लिए भी लाइन में लगरकर परेशान होना पड़ रहा है। लगातार खाद की रैक लग रही है- कृषि उप संचालक जवाहर लाल कार्से के मुताबिक खरीफ सीजन के लिए कुल 24 हजार 500 मेट्रिक टन खाद की जरूरत है, जिसमें से 22 हजार मीट्रिक टन खाद पहले ही आ चुकी है। उन्होंने बताया कि जिले में लगातार खाद की रैक लग रही है और किसानों को उनकी जरूरत के अनुसार खाद उपलब्ध कराई जा रही है। यहां मिलेगा यूरिया- जिला विपणन अधिकारी योगेश मालवीय ने बताया कि बुधवार सुबह 10 बजे से यूरिया का वितरण शुरू होगा। विपणन संघ गोदाम हरदा, टिमरनी और छीपाबड़ के अलावा रहटालाप, खिरकिया और एमपी एग्री के माध्यम से भी यूरिया मिलेगा।

10 साल की बच्ची ने बनाई अपहरण की कहानी

रीवा में टेस्ट छूटा तो वीडियो देख रवानाटक, सीसीटीवी में साइकिल से जाती दिखी

रीवा (नप्र)। रीवा में एक 10 साल की बच्ची के कथित अपहरण का मामला मंगलवार को सुलझ गया। पुलिस जांच में पता चला कि बच्ची ने मोबाइल में वीडियो देखकर अपने अपहरण की झूठी कहानी गढ़ी थी। बच्ची स्कूल में किसी कारण से टेस्ट नहीं दे पाई थी। उसे डर था कि टीचर उसे डांटेंगी। घटना रीवा शहर के चोरहटा थाना क्षेत्र की है। परिजनों ने 4 अगस्त को थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में उन्होंने कहा था कि उनकी बेटी का दो अज्ञात बाइक सवारों ने अपहरण कर लिया है। नगर पुलिस अधीक्षक रितु उपाध्याय ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए बच्ची की तलाश में शहर भर के करीब 20 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। इन फुटेज में बच्ची खुद अपनी साइकिल से जाती हुई दिखाई दी, जो परिजनों के दावे से बिल्कुल उलट था।

स्कूल के लिए निकली, भटकती रही

पुलिस ने बताया कि बच्ची का 29 जुलाई को स्कूल में टेस्ट था। वह किसी कारणवश नहीं दे पाई। इसके बाद सीधा स्कूल 4 अगस्त को गई। इन बीच के दिनों में वो सेहत खराब होने का बहाना बनाती रही। सोमवार को वो घर से तो स्कूल के लिए निकली, लेकिन डर की वजह से स्कूल जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। इसलिए स्कूल जाने की जगह साइकिल से दूर भटकती रही।

शाम को घबराई हुई घर पहुंची- बाद में शाम को बच्ची घबराई हुई घर पहुंची। परिजनों से कहा कि दो लोगों ने मेरा अपहरण कर लिया था। फिर परिजन बच्ची को लेकर सीधा थाने पहुंचे। बच्ची सोमवार को बहुत थकी हुई थी। उसकी बातें पुलिस को संदेहास्पद लगीं। पुलिस ने मंगलवार को उसके बयान दर्ज किए।

बढ़ता बहनों का विश्वास
बढ़ती घर-घर
खुशियां



नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री



डॉ. मोहन यादव
द्वारा

1.26 करोड़ से अधिक लाड़ली बहनों को
रक्षाबंधन का उपहार

₹1859 करोड़ की राशि का अंतरण

आज आयेंगे हर बहन के खाते में
₹250 रक्षाबंधन शगुन और
प्रतिमाह के **₹1250** सहित कुल **₹1500**

28 लाख से अधिक बहनों को गैस सिलेंडर रीफिलिंग
के लिये **₹43.90** करोड़ की सहायता

7 अगस्त 2025 | अपराह्न 2:30 बजे
मंडी प्रांगण, नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़

D-11075/25

सीधा प्रसारण

webcast.gov.in/mp/cmevents

@Cmmadhyapradesh
@jansampark.madhyapradesh

@Cmmadhyapradesh
@jansamparkMP

jansamparkMP